खण्ड-07 सत्र-05 / अंक-70

सोमवार 08 अप्रैल, 2024 / 19 चैत्र, 1946 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

पाँचवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-05 में अंक 50 से अंक 70 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-5 सोमवार, 08 अप्रैल, 2024/19 चैत्र, 1946 (शक) अंक-70

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	3-23
3.	ध्यानाकर्षण (नियम-54)	24-82
4.	अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)	83-103

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 सोमवार, 08 अप्रैल, 2024/19 चैत्र, 1946 (शक) अंक-70

दिल्ली विधान सभा

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अजेश यादव
2. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
3. श्री अब्दुल रहमान
4. श्री धर्मपाल लाकड़ा
5. श्री दुर्गेश कुमार
6. श्री गिरीश सोनी
7. श्री गुलाब सिंह
8. श्री जय भगवान
9. श्री करतार सिंह तंवर
10. श्री महेंद्र गोयल
11. श्री नरेश यादव
12. श्री प्रीति जितेंद्र तोमर
13. श्री प्रवीण कुमार
14. श्री ऋतुराज गोविंद
15. श्री राजेश गुप्ता
16. श्री राजेंद्र पाल गौतम
17. श्री रोहित कुमार
18. श्री शरद कुमार चौहान
19. श्री संजीव झा
20. श्री सोमदत्त

21. श्री शिव चरण गोयल
22. श्री एस. के. बग्गा
23. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
24. श्री अजय दत्त
25. श्री अभय वर्मा
26. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
27. श्री अजय कुमार महावर
28. श्री बी. एस. जून
29. श्री जितेंद्र महाजन
30. श्री महेन्द्र यादव
31. श्री मदन लाल
32. श्री मोहन सिंह बिष्ट
33. श्री ओमप्रकाश शर्मा
34. श्री प्रलाद सिंह साहनी
35. श्री रघुविंदर शौकीन
36. श्री राजेश ऋषि
37. श्री सुरेंद्र कुमार
38. श्री विजेंद्र गुप्ता
39. श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–5 सोमवार, 08 अप्रैल, 2024/19 चैत्र, 1946 (शक) अंक–70

दिल्ली विधान सभा

सदन 11.18 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगणों का स्वागत है। विशेष उल्लेख (नियम–280) श्रीमान मोहन सिंह बिष्ट जी।

विशेष उल्लेख (नियम 280)

श्री मोहन सिंह बिष्टः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा करावल के अन्तर्गत अधिकतर कॉलोनियां अन–ऑथोराइज्ड तथा रेगूलराईज की श्रेणी में आती है जिसमें कि विकास कार्य एमएलएलैड के द्वारा किया जाता है। पिछले दिनों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा इन क्षेत्रों में विकास कार्य करने के लिए एक लिखित आदेश जारी कर दिया गया है कि पहले सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेनी होगी तभी उन क्षेत्रों के अंदर विकास कार्य होगा। पिछले दिनों के अंदर करावल नगर के अधिकतर कालोनियां जो अन–ऑथोराईज्ड कालोनियां

जिनमें डीएसआईआईडीसी द्वारा कार्य किया जाता था, दिल्ली सरकार द्वारा अनाधिकृत कालोनियों के विकास के लिए बजट ना देने के कारण उन कालोनियों में विकास कार्य नहीं हो रहा है और लोग नारकीय जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे विधान सभा करावल नगर के अंतर्गत विकास कार्य करवाने के लिए यदि विधायक निधि जाती है तो अनापत्ति प्रमाण ना मिलने के कारण विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। जिन कालोनियों में बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा विकास कार्य करने के लिए पैसा दिया गया था, उन कालोनियों में भुगतान ना करने के कारण ठेकेदारों ने आधे-अधूरे कार्य छोड़ दिये हैं। बाढ़ नियन्त्रण विभाग, दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा बजट उपलब्ध कराने के लिए डिविजन-IV के माध्यम से ठेकेदारों की पेमेंट नहीं की जा रही है। मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने जान-बूझ करके काम को रोकने का षडयंत्र अपनाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, ये आपके साथ भी हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है। यदि आप काम डीएसआईआईडीसी से करा रहे हैं, यदि डीएसआईआईडीसी को फंड नहीं मिला तो एमसीडी ने एक ऑर्डर निकाल दिया है जब तक डीएसआईआईडीसी और एमसीडी से आप एनओसी सर्टिफिकेट नहीं लायेंगे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते।

माननीय अध्यक्षः हो गया। पढ़ दिया, पढ़ दिया बात कह दी सारी।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। सर जो हमारी परेशानी है उसको आपके सिवाय कौन सुनेगा। सर मेरा इसमें कहने का निवेदन ये है यदि एमसीडी के पास वो लैंड आती ही नहीं है, अन-ऑथोराईज्ड कालोनिज की परिधि में वो लैंड है तो उस पर एनओसी का क्या मतलब है। मेरा सीधा-सीधा कहना है कि सरकार एमसीडी को निर्देश दे और उन डिपार्टमेंट्स को निर्देश दें, जैसे बाढ़ नियंत्रण विभाग है। यदि उनकी लैंड नहीं है तो उसमें एनओसी देने का कोई औचित्य नहीं है, ये मैं आपके माध्यम से ऐसा ऑर्डर जाये ये मैं निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान अभय वर्मा जी।

श्री रामबीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय 280 को स्थगित करो। जल बोर्ड में बड़ा भारी घोटाला हुआ है। हजारों करोड रूपये का घोटाला हुआ है उस पर चर्चा हो। जल बोर्ड घोटाले पर चर्चा हो। अगर इस सदन में चर्चा नहीं होगी तो कब होगी। जल बोर्ड घोटाले पर चर्चा करवाईये अध्यक्ष जी। जल बोर्ड घोटाले पर।

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी सदन विधिवत चालू है। मेरे पास कोई..

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः अध्यक्ष जी, जल बोर्ड..

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में शोर शराबा किया गया तथा विरोध में तख्तियां दिखाई गईं।)

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः माननीय विपक्ष के सदस्यों को अगर 280 में भाग नहीं लेना है। 280 में भाग नही लेना है, आप बाहर जा सकते हैं।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः 70 हजार करोड के नुकसान में है जल बोर्ड।

श्री रामबीर सिंह बिधूड़ीः दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय नेता, विपक्ष से प्रार्थना कर रहा हूं सदन को शान्तिपूर्वक चलने दें। सदन को शान्तिपूर्वक चलने दें।

...व्यवधान...

श्री रामबीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष जी जल बोर्ड घोटाला हुआ है उस पर चर्चा कराओ।

माननीय अध्यक्षः नहीं ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः सीवर लाइन भरे पड़े हैं।

...व्यवधान...

माननीय सभापतिः मार्शल्स। मार्शल्स।

...व्यवधान...

माननीय सभापतिः मार्शल्स। अभय वर्मा जी को..

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः दिल्ली के लोग परेशान है। हताश हैं। अध्यक्ष जी जल बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा जरूर कराईये। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए बिधूड़ी जी बाहर जाईये, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, माननीय सदस्यों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं नेता विपक्ष, सभी बाहर जायें, नहीं तो मार्शल्स बाहर करें सभी को।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में शोर शराबा जारी रखा गया।)

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बाहर जाईये। बाहर बैठिये। मार्शल्स बाहर करें, जल्दी करे। नाम लूं, श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, ओम प्रकाश जी, महाजन जी, महावर जी, अभय वर्मा जी, बाजपेयी जी बाहर करिये।

...व्यवधान...

(उपरोक्त सभी सदस्यों के साथ-साथ विपक्ष के बाकी सदस्य भी नारे बाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए।)

माननीय अध्यक्षः चलिये जल्दी करिये। जल्दी करिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जिस दिन जल बोर्ड पर चर्चा होनी होती है उस दिन भाग नहीं लेते हैं, आज जल बोर्ड की बात कर रहे हैं। भूपिन्द्र सिंह जून जी।

श्री बी एस जूनः धन्यवाद सर। अध्यक्ष जी दिल्ली में डेली तापमान बढ़ रहा है। 37-38 डिग्री टैम्परेचर हो चुका है। तापमान के साथ-साथ पानी की कमी, सीवर ब्लॉकेज की कम्पलेंटस, वो भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। दिल्ली जल बोर्ड क्लेम करता है कि हम डेली 995 एमजीडी वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो वो पानी अगर लोगों को नहीं मिल रहा है तो कहां जा रहा है? अगर कहीं लीकेज है तो वो दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेवारी है कि वो उसको ठीक करे। अगर कहीं चोरी है तो दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेवारी है वो उसको ठीक करें। अब दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बोलो तो एक अजीब सा तर्क देते हैं कि पहली बात तो ये है कि जी एमसीसी लागू है Model Code of Conduct तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम लेबर हायर नहीं कर सकते। हमारे पास सीवर क्लीनिंग मशीनों की शार्टेज है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम कोई अगर immediate emergency repair का काम है वो नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें परमिशन चाहिए। तो सर ये Model Code of Conduct तो 4 जून तक चलेगा देश में, तो लोग कहां जाये इस गर्मी में, कहां से उनको पानी

मिलेगा? डेली contaminated water की कम्पलेंटस आ रही है। लोग एमएलऐज ऑफिस में आ रहे हैं। लेकिन ये कोई जवाब नहीं है कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम हैल्पलैस हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली जल बोर्ड को पैसा नहीं दिया गया। पीछे पता लगा थोडा बहुत पैसा भी रिलीज हुआ है। तो ये लोग काम क्यों नहीं करते? अब मैंने एक एसीई (ई-9) है जब उससे बात की, मैंने कहा भई तुम काम क्यों नहीं करते, बोले जी Model Code of Conduct है उसमें काम नहीं कर सकते। मैंने कहा ये तो essential service है जो काम कभी नहीं रूकता। तो कहता है आपको जिसको कम्पलेंट करनी है कर दीजिए। ये तो कन्डक्ट है सर जल बोर्ड के अधिकारियों का। उनको लगने लगा है कि इलैक्शन का टाइम है और उनको शायद ये भी गलतफहमी है कि ये असेम्बली रहे ना रहे चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो गए। चीफ मिनिस्टर के अरेस्ट के बाद एक दम से उनका कंडक्ट, बिहेवियर चेंज हो गया। तो टैंकर्स की बात करें जैसे मेरी विधान सभा का 75 परसेंट जो है एरिया टैंकर्स पर या बोरवेल पर डिपैंड करता है। टैंकर्स कम कर दिये। दस बोरवल या दस से पन्द्रह बोरवेल डेढ साल हो गया सैंक्शन हुए, आजतक वो बोरवेल नहीं हुए। तो इन हालात में लोग पानी कहां से लायें। उसमें सरकार की भी बदनामी हो रही है, उसमें पार्टी की भी बदनामी हो रही है और culprit कौन है, दिल्ली जल बोर्ड के आफिशियल्स। तो मेरा आपके माध्यम से ये ही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को कहा जाए कि भई तुम कम से कम जो essential services है उसमे Model Code of Conduct का बहाना ना ले के काम करने से

मना ना करो, लोगों को contaminated water से राहत दिलवाओ और सीवरेज की जो प्रोब्लम्स है उनको साफ करो। अगर सीवर भरे रहेंगे तो पानी भी सर मिक्स हो कर आयेगा और उससे बीमारियां भी फैल सकती हैं। तो आपसे ये ही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि उनको डायरेक्शंस दी जाये कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाये और इनका जो बिहेवियर है, दिल्ली जल बोर्ड ऑफिशियल्स का उनका cordial होना चाहिए जनता के साथ भी और चुने हुए विधायकों के साथ भी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।

माननीय अध्यक्षः श्री राजेश गुप्ता जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई अभी आप पर्ची लिखकर भेजिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं पर्ची लिखकर भेजिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई रवि जी बोल रहा हूं पर्ची लिखकर भेजिये मैं बोलना चाहता हूं।

श्री विशेष रविः ठीक है सर।

माननीय अध्यक्षः राजेश गुप्ता जी। (अनुपस्थित)। श्रीमान रोहित कुमार जी।

श्री रोहित कुमारः धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने नियम 280 के तहत मुझे अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का यहां पर सदन में मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि अभी लगभग छः महीने से त्रिलोकपुरी के अंदर सीवर और पानी की गम्भीर समस्या बनी रही। जगह-जगह मल-मूत्र गलियों में बहता रहा। उसके समाधान के लिए जो प्रयास किये गए जल बोर्ड के द्वारा वो पूरी तरीके से नाकाफी थे। अब गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है माननीय अध्यक्ष जी। तो मैं बताना चाहता हूं कि त्रिलोक पुरी में पानी की भारी किल्लत शुरू हो गई है अभी से। पानी को दूर तक पहुंचाने के लिए जो टेल एंड के इलाके हैं वहां के लिए प्रयास किया गया था पिछले साल। बड़ी मशक्कत करने के बाद में 23 ब्लॉक त्रिलोक पुरी स्थित जल बोर्ड के यूजीआर के लिए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी जिसकी क्षमता पांच एमजीडी है लगभग और भागीरथी से जो पानी यहां पर आता है ये त्रिलोकपुरी विधान सभा दिल्ली के बार्डर पर है, आखिर में पानी पहुंचता है, कम पानी पहुंचता है जिसके चलते वहां पर गम्भीर समस्या रहती है। तो माननीय अध्यक्ष जी, पिछले साल दस करोड रूपये की लागत से एक प्रोजेक्ट पूरा किया गया था। जिसमें आठ ट्यूबवेल म्यूर विहार फेस-वन मैट्रो स्टेशन के पास में यमुना खादर में लगाये गए थे और पानी की पाइप लाइन के जरिये एक एमजीडी पानी की अतिरिक्त व्यवस्था त्रिलोकपुरी ब्लॉक नं.-23 के यूजीआर तक की गई थी माननीय अध्यक्ष जी। पिछले साल

मई के अंदर वो काम पूरा हो गया था यानि की पिछले साल गर्मियों में ही त्रिलोकपुरी वासियों को एक एमजीडी पानी अतिरिक्त मिल जाता। सारा काम पूरा होने के बाद भी मशीनरी सारी लग गई है, ट्यूबवेल लग चुके हैं पाइप लाईन डल गई है, उसके बाद भी अभी तक ये ट्यूबवेल चालू नहीं हुए क्योंकि इसमें बिजली का कनैक्शन नहीं हो पाया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को पानी पहुंचाने जैसा नेक काम यहां पर होने जा रहा था, उसमें भी डीडीए ने अडंगा लगा दिया। डीडीए ने एनओसी का बहाना बनाकर, ओजोन का बहाना बनाकर यहां पर जल बोर्ड को लिखित के अंदर चेतावनी भेजी है कि आपने यहां पर बगैर एनओसी के जो काम करा है ट्यूबवेल लगाये हैं आप को भारी हर्जाना देना होगा। बीएसईएस यहां पर बिजली का कनैक्शन लगाने को तैयार नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी को भी मैंने लिखा है इसके लिए। सदन में पहले भी मैंने इसके लिए आवाज उठाई थी। तो मेरा पुनः माननीय अध्यक्ष जी, त्रिलोकपुरी वासियों की ओर से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस ट्यूबवेल के लिए कनैक्शन यहां पर दिलाया जाये, जो आठ ट्यूबवेल लगाये गए हैं और ये बड़ा गम्भीर मामला है कि जनता के जो खून पसीने की टैक्स पेयर की कमाई का जो पैसा है वो दस करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं। लोगों की सहूलियत के लिए लोगों को पानी पहुंचाने के लिए उसके बाद भी एक बिजली का कनैक्शन नहीं हो पा रहा है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है त्रिलोकपुरी ब्लॉक नम्बर-2 की बात करें, ब्लॉक नं.-3 की, 31 ब्लॉक की बात करें, 32 की, ब्लॉक नम्बर-20 की न्यू अशोक नगर की बात करें, ई-ब्लॉक की,

डी-ब्लॉक की, सी-ब्लॉक की हर जगह पर पानी की भारी किल्लत होनी शुरू हो गई है। जहां पर पानी कम पहुंच पा रहा है वहां पर गंदे पानी की शिकायतें आने लगी है। तो माननीय अध्यक्ष जी, पुनः मैं दूसरी बार ये सदन में ये ही आग्रह कर रहा हूं और ये दोबारा मैं फिर से निवेदन माननीय मंत्री जी से सरकार से करना चाहता हूं कि यहां पर जो ट्यूबवेल लगे हैं, मैट्रो स्टेशन फेस-1 के सामने यमुना खादर में आठ ट्यूबवेल लगे हैं इनके लिए जल्द से जल्द कनैक्शन बिजली का दिलाया जाये ताकि त्रिलोक पुरी वासियों को पानी पहूंच सके, उनको पानी मिल सके। मैं पुनः आपसे हाथ जोडकर मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं सदन से। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो इतना गम्भीर विषय सदन में मुझे उठाने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमती प्रीति जितेंद्र जी।

श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमरः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 के तहत मुझे मेरी त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र की बहुत ही गम्भीर समस्या पर बोलने का मौका दिया। मेरी विधान सभा के त्रिनगर वार्ड में करीब अध्यक्ष जी तीन सौ गलियां हैं, जिनमें से करीब सौ गलियों में सीवर जाम और ओवर फ्लो की समस्या लगातार बनी हुई है। यानि त्रिनगर वॉर्ड के 33 परसेंट हिस्से में हमेशा सीवर बहता रहता है। सीवर के मेन हॉल से गाद निकालने वाले कर्मचारी ना होने के कारण शकूरपुर गांव, राम पुरा गांव, त्रिनगर, राजा पार्क, महेन्द्रा पार्क और प्रीतमपुरा गांव सहित पूरी विधान सभा क्षेत्र में सीवर की स्थिति बहुत खराब हो गई है। पानी का प्रेशर कम होने तथा सीवर मेन हॉल

लबालब भरे होने ओवर फ्लो होने के कारण त्रिनगर वार्ड, शकूरपुर गांव, श्रीनगर, राजा पार्क प्रीतमपुरा गांव, महेन्द्रा पार्क और शकूरपुर गांव से प्रतिदिन 50 से ज्यादा गंदा पानी आने की शिकायतें मेरे कार्यालय में आती रहती हैं। मेरा कन्सर्ड मिनिस्टर से अनुरोध है अध्यक्ष जी कि जल्द से जल्द मेरी इस समस्या का हल निकाला जाये। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान साहनी जी।

श्री प्रलाद सिंह साहनीः अध्यक्ष जी आपने बोलने का मौका दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से हमारे यहां पानी की बहुत कमी हो रही है और खास करके रमजान के दिनों में मुस्लिम एरिया के अंदर पानी का स्पेशल अरेंजमेंट होता था। अब मेरा ख्याल ऐसा अरेंजमेंट हुआ है कि मुस्लिम एरिये का पानी बंद कर दो। रमजान के दिनों के अंदर पुराने एक्सपर्ट जेई लगाया करते थे। मैंने इनको लिखकर भी भेजा दो जगह पर मटिया महल में, बल्ली मारान में सब जगह का जेई बदलकर पुराने जेई लगा दिये गए। जब हमने इनको कहा तो इन्होने हमें ना तो कोई जवाब दिया, ना कुछ हुआ। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये पिक एंड चूज क्यों करते हैं। किसी constituency में काम करना है, किसी में नहीं करना। मैम्बर (ए) एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं उन्होंने चुन-चुन कर जेईज को ट्रांसफर किया है, जेईज को अपने पास रखा है। फिर दोबारा उनको तीन-तीन दा बुलाया है तो हमारे एरिये में ऐसा क्यों नहीं हुआ ताकि हमारे पानी की और सीवर की प्रोब्लम हल हो सके। मैं आपके मार्फत पूछना चाहता हूं कि मैम्बर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं विस्तार से बताते कि उनका काम सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ

मुस्लिम एरिया का कहने की बात करते हैं जबकि मुस्लिम एरिया मेरा भी है। मेरी constituency के अंदर तमाम मुसलमान रहते हैं। जामा मस्जिद का एरिया है इसके अंदर उसको सफाई और पानी दोनों से वंचित रखा गया है। मेरा आपसे अनुरोध है खास करके मैम्बर एडमिनिस्ट्रेशन, कि मैं कह नहीं सकता लोग, इमाम साहब से भी मेरी बात हुई जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वहां के लोग मैं कहना नहीं चाहता जो वो वहां इस्तेमाल करते हैं मैम्बर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मैंने कहा जी इस-इस तरीके आपके मुस्लिम मैम्बर है। कहते हैं वो मुस्लिम नहीं xxx[1] है xxx[1]। तो मेरा कहने का मतलब है कि इलाके अंदर इतनी गंदी बातें पैदा हो रही है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस चीज को ध्यान से देखें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान महेंद्र गोयल जी।

श्री महेंद्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आज पूरा का पूरा सदन तकरीबन-तकरीबन एक ही मुद्दे पर ज्यादातर बात हो रही है, गंदे पानी की समस्या से, इस सीवर की समस्या से। ये कुछ षड़्यंत्र के तहत ज्यादा है इस समय में। इस समय के अंदर आकर जब दिल्ली सरकार लगातार बीस हजार लीटर पानी हर घर को फ्री में दे रही है और लगातार नौ साल तक दिया। इस चुनाव के मौके के ऊपर आकर चार-पांच महीने पहले से तीन महीने पहले से फिल्डिंग रचनी स्टार्ट कर दी। आज कहीं पर सीवर की समस्या पैदा हो रही है, कहीं पर गंदे

[1] चिन्हित शब्द अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन की कार्यवाही से हटाए गए।

पानी की समस्या पैदा हो रही है, कहीं पर पानी की सप्लाई की शार्टेज हो रही है। ये समस्या अपने आप नही हुई, ये समस्या एक प्रायोजित ढंग के साथ में हुई है, चुनाव के समय में हुई है। तीन महीने पहले से, चार महीने पहले से एरिये से लेबरों को हटा लिया, मशीनों को हटा लिया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां पर लगातार नौ साल तक हम हर घर को पीने के लिए बीस हजार लीटर पानी फ्री में दे रहे हैं। ऐसा क्या हो गया इस समय के अंदर सर्दियों के अंदर सप्लाई की शार्टेज हो गई। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक गंदी राजनीति के तहत ये षड़्यंत्र रचा जा रहा है। मेरे यहां पर 107 किलोमीटर की लाइन डलनी थी, सीवर की लाइन, जिसके अंदर तकरीबन-तकरीबन 152-53 किलोमीटर की लाइन पूरी हो गई। सात किलोमीटर की लाइन वो बची हुई है जहां पर 10 फुट की गलियां हैं। अमृत फंड के तहत ये फंड था। जिसके लिए जो बचत होती है उसके अंदर बाकी के बचे हुए वो काम हो जाते है। लेकिन केन्द्र सरकार ने उसके ऊपर भी रोक लगा कर वो भी पैसा वापिस ले लिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। इस सदन को कहीं ना कहीं अपनी आवाज को राष्ट्रपति जी तक भी पहुंचाये और जनता के बीच में भी ये आवाज आपको लेकर जानी पड़ेगी। इस समय के अंदर दिल्ली के अंदर जो खेल चल रहा है बहुत घटिया राजनीति का, राजनीति का ही नहीं ये घटिया सोच का जिस प्रकार से खेल चल रहा है ये हमारे ही लिये नहीं उन लोगों के लिए भी नाश का कारण बनेगा, नाश करने वाला बनेगा, क्योंकि इस समय में हर आदमी दुखी है। हमारी बहन बेटियां पानी पीती हैं, मिनट में बीमार हो जाती हैं।

सीवर का पानी उसके साथ में मिक्स कर रहे हैं। मेरे यहां पर बहुत सी लाइनों के अंदर कट्टे फंसा देते हैं सीवर लाइन के अंदर ताकि वो पानी रूक जाये। मेरा आपसे एक ही निवेदन है मेरे एरिये के अंदर सात किलोमीटर की लाइन के लिए मैंने लिखकर दे रखा है जो कि जुलाई से फाइल चली हुई है। हमारे वाईस चेयरमैन ने भी उस पफाईल के लिए मंजूरी दे दी है। आज तक उसका टेंडर नही लगा। माननीय मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने भी अप्रूवल दे दी लेकिन आज तक भी वो टेंडर नहीं लगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस सदन के अंदर मैंने पहले भी आवाज उठाई थी और बहुत से साथियों ने आवाज उठाई थी कि सुपर सक्कर मशीनें जो जो एरिये में से हटा ली गईं उनके लिए फिर से नया टैण्डर करें, एरिये के अंदर जो भी एडवांस टैक्नोलॉजी की मशीनें हैं उनको दिया जाए और सीएम साहब ने एक बहुत अच्छी पहल की थी पहले एक छोटी गाड़ी जो छोटी छोटी गलियों के अंदर भी आराम से चली जाती थी वो गाडियां बहुत कम हो चुकी हैं, कोई खराब हो चुकी है। राजेंद्र पाल गौतम जी उस समय में माननीय मंत्री होते थे मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि उस समय में आप लोगों ने सीएम साहब के कहने से वो गाडियां लोगों के हितों के लिए दी थीं तो उन गाड़ियों की संख्या भी डबल में होनी चाहिए कम से कम में तब जाके इस दिल्ली का काम सुधरेगा। नियम 280 के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया था इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज इस सदन के अंदर तकरीबन तकरीबन सभी साथी जो पानी की समस्या से

जूझ रहे हैं गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, सीवर लाइन की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इस पर संज्ञान लेते हुए आप कोई उचित कदम उठाने का निर्णय लेगें। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमान विशेष रवि जी।

श्री विशेष रवि: धन्यवाद अध्यक्ष जी। सर मेरे को जो जून साहब ने जो विषय उठाया था उसी पे बस दो बात बोलनी है कि अभी गर्मी का समय है मौसम गरम हो रहा है और आगे और गरम होने वाला है तो जलबोर्ड हम सब जानते हैं कि वो जो आवश्यक जो एसेंशियल जो काम होते हैं उन्हीं को जो है करने के लिए डिपार्टमेंट ये बना हुआ है। अगर चुनाव का Model Code of Conduct का बोल के जलबोर्ड ये कहेगा कि हम जो है गंदे पानी की कंपलेंट अटैंड करनी है उस में कोई नया पाइप डालना है उसके टैंडर नहीं कर सकते हैं या किसी गली के अंदर जो है पानी की समस्या है या कहीं पे ऑलरेडी पानी की समस्या है और जलबोर्ड ने स्कीम बना रखी है, उसका टैंडर भी हो गया है लेकिन वर्क अवार्ड नहीं हुआ है, उसको ये बोलेंगे कि एमसीसी की वजह से हम वर्क अवार्ड नहीं कर सकते हैं, कहीं पे सीवर लाइन की मशीन लगनी है वहां पर सीवर चॉक हो रखे हैं और जल बोर्ड ये कहेगा कि हम जो हैं टैंडर कॉल नहीं कर सकते या फिर वहां पर नया काम नहीं ले सकते हैं तो सर ऐसा अगर जल बोर्ड का जवाब ये होगा तो उससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जलबोर्ड का काम जो है वो सारा जो बहुत ही जरूरी काम होता है, ग्राउंड पे उसका काम करने का होता है। मुझे लगता है कि इसको जो है जो

Model Code of Conduct की गाइड लाइंस हैं उनको हमें देखना चाहिए और जो मेरे पास जानकारी आई है जैसे पीडब्ल्यूडी के हमारे एक्सईएन हैं मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने अभी कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी वर्क अवार्ड किए हैं, उन्होंने अपने एरिया के अंदर नालों की सफाई को लेकर क्योंकि इस दौरान अब ये जो चुनाव चलेगा इस समय मानसून भी आने वाला है तो उन्होंने नालों की सफाई समय से हो उन्होने Code of Conduct के बाद भी वर्क अवार्ड किया है। उनका ये कहना है कि मैं वेट नहीं कर सकता कि कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा उसके बाद मैं नालों की सफाई करूंगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः साहनी जी बैठिए, महेंद्र जी, चलिए।

श्री विशेष रविः तो सर मेरा ये कहना है कि इस बारे में जो है एक गाइड लाइन जो है या तो यहां से या फिर माननीय मंत्री जी इशु करें कि जो जरूरी काम हैं जहां पर काम नहीं किया तो वहां पर जो है वो संभव नहीं है कि इधर चल पाएगा दो तीन महीने वहां पर जल बोर्ड जो है वो काम करे। चाहे तो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेकर काम करे या वैसे ही अपने आप काम करे जैसे पीडब्ल्यूडीया बाकी डिपार्टमेंट कर रहे हैं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान लाकड़ा जी।

श्री धर्मपाल लाकड़ाः अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः 280 में आपने दिया था ना मुझे 280 में बोलने के लिए।

श्री धर्मपाल लाकड़ाः हां जी।

माननीय अध्यक्षः हां बोलिए।

श्री धर्मपाल लाकड़ाः बोल रहा हूं जी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मुण्डका विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बोलना चाहता हूं। मेरे मुण्डका विधानसभा में तकरीबन वार्ड 32 और 33 में आज तक सीवर लाइन डली नहीं है और पिछले दो से ढाई साल से जब भी हम रोड़ नाली के लिए बजट मांगते हैं तो अधिकारी मुझे जवाब देते हैं कि यहां पहले सीवर लाइन डलनी प्रस्तावित है, एस्टीमेट बन चुका है, टैंडर लग चुका है और पेमेंट ना मिलने के कारण आज तक अवार्ड नहीं हो पाया है जिसमें मेरे क्षेत्र की जो है वार्ड 32 में कंझावला एरिया जिसमें रानीखेड़ा में लगभग दस गांव जैसे कराला, कंझावला, मजरी, लाडपुर, टटैसर, जौन्ती, गढ़ी रंडाला, निजामपुर सावदा और झिमरपुरा इत्यादि ये गांव हैं व अनेकों कालोनियां जैसे उदय विहार, रूपाली एंक्लेव, महावीर विहार, बलदेव विहार, उत्सव विहार, आनंदपुर धाम, शिव विहार, वर्धमान एंक्लेव, शहीद भगतसिंह कालोनी, उपकार विहार इत्यादि और एक बहुत बड़ी जे.जे. कालोनी है जिसका नाम सावदा जे.जे. कालोनी है जिसमें आज तक सीवर की लाइन ही नहीं है, सोलह कालोनियां कच्ची कालोनियां, ग्यारह गांव और एक जे.जे. कालोनी जिनका पैसे के अभाव में पिछले दो से ढाई साल से वर्क अवार्ड नहीं

हो पाया है और गलियां, नालियां बनाने के लिए पैसा मांगता हूं तो मुझे ये जवाब दे दिया जाता है कि यहां सीवर लाइन डलनी प्रस्तावित है, सीवर लाइन डलने के बाद होगा। अब उसके बाद बीजेपी वाले या हमारे एलजी साहब वहां जा जाकर के उन गांव में, कम से कम आठ गांव में उन्होनें डेरा डाला है डीएम, एसडीएम ने और ये बुराई देते हुए कि भई दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही और करने वो नहीं दे रहे क्योंकि बजट नहीं दिया जा रहा अवार्ड नहीं होने दिया जा रहा, सीवर लाइन डल नहीं पा रही जिसके कारण रोड़ और नाली भी नहीं बन पा रही, कोई बजट नहीं मिल पा रहा। मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है इसको प्रायर्टी पे उठाया जाए और यहां विशेष ध्यान दिया जाए। मेरा आपसे ये अनुरोध है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः ध्यानाकर्षण नियम 54

...व्यवधान...

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्षजी आपकी इजाजत हो ता थोड़ी सी बात रखना चाहता हूं। हमारे पर यहां जितने जेई,एई हैं सारे नए आ गए हैं इनको किसी area का नहीं मालूम है। ऐसे ही बहुत सारी विधानसभाओं में हुआ है कि जेई, ऐई सब नए आ गए एक्सईएन तक नए आ गए उनको एरिये की जानकारी नहीं है ना समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। इस प्रश्न को एक बार आपने भी उठाया था। तो मेरी आपके द्वारा ये अनुरोध है कि जेई, ऐई जो पुराने थे उनको दोबारा लाया जाए कुछ नए रखे जाएं ताकि वो लोग एरिये को समझ सकें उनके द्वारा,

अब बिल्कुल नए हैं सर उनको कुछ पता ही नहीं है हम भेजते हैं वहां वो पहुंच जाते हैं कहीं और। तो आपसे अनुरोध है कि इस काम को करवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी।

माननीय अध्यक्ष: श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ता: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया 280 में अपनी विधानसभा पर बोलने का। अध्यक्ष जी मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो झुग्गी बस्तियां थीं उसमें आज से पहले बहुत कम लोग इतना ध्यान देते थे जितना उन्होंने दिया। मेरे क्षेत्र के अंदर ऐसी बहुत सारी झुग्गी बस्तियां थी जिसमें पानी की पाइप लाइन लगभग थी ही नहीं या बहुत खराब थी, टंकियां रखवा दी गई थीं, लोग दूर दूर से भर के आते थे। तो हमने बहुत सारी जगह पर पानी की लाइनें डाली लेकिन चूंकि उसको काफी समय हो गया है, छह सात साल हो गए हैं और उनमें से बहुत सारी पानी की लाइनें अब बहुत खराब हो गई हैं, जर्जर हो गई हैं, उनमें जंग लग गए हैं, टूट गई हैं या तोड़ दी गई हैं तो उसमें मैं आपके माध्यम से चाहता था कि जल बोर्ड तक ये बात जाए और वो उनको बदलें। मैं कुछ क्षेत्र इसमें पढ़ना चाहता हूं जैसे पत्थर वाला बाग जे.जे. कालोनी इसमें माननीय मंत्री जी भी वहां पे आई थीं इन्होंने भी आश्वासन दिया था। जे थर्ड ब्लॉक जे.जे. कालोनी के और ए ब्लॉक एल ब्लॉक जे.जे. कालोनी, वजीरपुर इंडस्ट्रीयल एरिया का ए ब्लॉक श्रीराम चौक, जगदम्बा मंदिर शहीद सुखदेव नगर गदा गढ़ यहां पानी की बहुत समस्या है। अब मैं कुछ दिन पहले देख के भी आया था इसके

अंदर तो एक लाइन डाली गई थी लेकिन एक और की इसमें जरूरत है। बी ब्लॉक मछली मार्किट अंबेडकर नगर चौक, बैटरी पार्क सत्संग कालोनी पार्वती चौक और बी 70 बी 46 ये सब वजीरपुर इंडस्ट्रीयल एरिया का है। जेरावाला बाग अशोक विहार फेस टू, सावन पार्क अशोक विहार फेस थ्री वजीरपुर गांव और शक्ति नगर एक्सटेंशन की कुछ झुग्गियां हैं जिसमें इन सभी लाइनों को डालने की जरूरत है। अब आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि आपने मीटिंग करी थी मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जो राजेश ऋषि जी ने जो सवाल उठाया उस पे आपने मीटिंग करी थी मैं उसमें मेरा सौभाग्य था आपने मुझे बुलाया था, मैं उसमें था तो आपको भी उन्होंने कहा था कि हम तीनों लोगों को नहीं बदलेंगे जो ग्राउंड पर रहते हैं। एक्सईएन, ऐई जेई इनमें से किसी एक को पुराने को छोड़ दें वो जिस मर्जी को छोड़ दें हम लोगों को किसी पर्टिकुलर आदमी से मतलब नहीं है। एक कोई भी अधिकारी जमीन पे रहने वाला एक्सईएन, जेई, ऐई पुराना रह जाए तो काम करने में थोड़ी आसानी होती है, नहीं तो लोग समझ भी नहीं पाते। तो आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण नियम 54 श्री राजेंद्रपाल गौतम जी, माननीय सदस्य दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिकों, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में दवाईयों की कमी और कुछ संबधित अधिकारियों के कारण अप्रैल 2024 से मोहल्ला क्लिनिकों में मुफ्त जांच सुविधाएं बंद होने की आशंका के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे श्रीमान गौतम जी।

ध्यानाकर्षण (नियम 54)

श्री राजेन्द्रपाल गौतमः बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 54 में विभिन्न अस्पतालों में डिस्पेंसरिज़ में मोहल्ला क्लिनिक्स में दवाइयों की संपूर्ण उपलब्धता ना हो पाने व मोहल्ला क्लिनिक में जांच रूकने की संभावना की ओर दिलाने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी दिल्ली में केन्द्र सरकार के हॉस्पिटल्स के लगभग पांच गुणा हॉस्पिटल्स दिल्ली की सरकार चलाती है। अनेकों पोलिक्लिनिक्स, अनेकों डिस्पेंसरीज़ और 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। पहले हॉस्पिटल्स को खुद लोकल परचेज करने का अधिकार होता था लेकिन उसमें भ्रष्टाचार के इस तरह के आरोप लगे और इस तरह की घटनाएं सामने आईं जिसकी वजह से सरकार ने निर्णय लिया कि सैंट्रली दवाइयों को प्रिक्योर करने का सिस्टम बनाया जाए और सीपीए का गठन करके central purchase शुरू हुआ। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी मैं बहुत शर्म के साथ और बहुत दुख के साथ पूरे सदन का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने सीपीए का टैंडर कर दिया था दवाइयों का लेकिन टैंडर करने के बावजूद एक साल पूरा हो गया और एक साल पूरे होने तक भी उस टैंडर को कंपलीट नहीं किया। कभी technical bids के नाम पर कभी किसी दूसरी वजह से उस टैंडर को finalize नहीं किया और एक साल हो गया टैंडर एक्सपायर हो गया। दवाइयां अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं पूरे ऑपरेशन के लिए दवाइयों से अलग और भी कई चीजों की जरूरत

पड़ती है और जब डाक्टर कहते हैं हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है आप मार्किट से खरीद के लाइए, इससे दिल्ली की सरकार जो ईमानदारी के साथ ना केवल दिल्ली के लोगों को चूंकि दिल्ली के अंदर केवल दिल्ली के लोग इलाज कराने नहीं आते बल्कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के आसपास के राज्य उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश वहां से भी लाखों लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली में आते हैं और ये तो मैं दिल्ली की सरकार का धन्यवाद करूंगा कि बिना पक्षपात के दिल्ली में बाहर के राज्यों से आने वाले लोगों को भी मुफ्त में ना केवल इलाज उपलब्ध करा रहे हैं बल्कि दवाइयां और ऑपरेशन से संबंधित सामग्री भी फ्री ऑफ कोस्ट दिल्ली सरकार उपलब्ध कराती है। लेकिन इस नौकरशाही के नकारात्मक रवैये की वजह से और नौकरशाही के द्वारा एलजी साहब के साथ मिल के दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कैबिनेट को बदनाम करने की नीयत से एक तरफ आप कहते हैं कि लोकल परचेज में घपला होता है इसलिए हम सीपीए लेकर आए और दूसरी तरफ सीपीए द्वारा टैंडर करने के बावजूद एक साल तक टैंडर को फाइनालाइज नहीं किया जाता और चारों तरफ त्राहिमाम मच जाता है, पेशेंट आ आकरएमएलए के कपड़े पफाड़ते हैं, एमएलए मंत्री के कपड़े फाड़ते हैं कि लोग आकर हमें शिकायत कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां नहीं हैं, आधी दवाइयां मिल रही हैं, आधी बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? मैं पूछना चाहता हूं माननीय चीफ सैक्रेट्री महोदय से, प्रिंसिपल सैक्रेट्री हेल्थ से वो बताएं क्या उन्होंने इस बात की जांच कराई कि सीपीए का टैंडर एक साल पूरा होने तक

भी फाइनालाइज क्यों नहीं हुआ और इस बीच दवाइयों के दाम बढ़ गए और वो टैंडर भी बेकार हो गया। भुगतना किसको पड़ा? भुगतना पड़ा दिल्ली के अंदर मरीजों को, भुगतना पड़ा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जो फंड्स अवेलेबल कराने में कभी कोताही नहीं बरतती, जो लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहती है, उस सरकार को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जो लोग इस बात के दोषी हैं, जिन्होंने मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने मरीजों की जीवन के साथ खिलवाड़ किया। माननीय अध्यक्ष जी आपकी और मेरी विधानसभा मिली हुई है, आपको पता है वहां पांच पांच हॉस्पिटल हैं एक एमसीडी का हॉस्पिटल है स्वामी दयानंद हॉस्पिटल जिसको जनरल हॉस्पिटल भी कहते हैं और चार दिल्ली की सरकार के हॉस्पिटल हैं जिसमें जीटीबी हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ईहभास जो व्यक्ति के दिमाग से संबंधित बीमारियों के लिए भारत में दो ही बड़े हॉस्पिटल हैं एक बैंगलोर का है और दूसरा ईहभास है। एक दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है और एक राजीव गांधी सुपर स्पेशियल्टी हॉस्पिटल है। माननीय अध्यक्ष जी आपको याद होगा कि दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल में पूरे देश से ही नहीं बल्कि दुनिया के बाहर के देशों से भी कैंसर का इलाज कराने लोग आते रहे हैं। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था, सरकार ने बहुत मन के साथ उस हॉस्पिटल को बनाया था। करोड़ों रूपये की मशीनें इंस्टॉल की थीं ना केवल दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में CAT SCAN सहित करोड़ों रूपये की मशीनें इंस्टॉल की थीं बल्कि

इसके साथ साथ राजीव गांधी सुपर स्पेशियल्टी हॉस्पिटल के अंदर भी करोड़ों रूपये की मशीनें इंस्टॉल की गई थीं लेकिन इस अफसरशाही के नकारात्मक या कहूं अपराधी प्रवृत्ति वाले कृत्य की वजह से ऐनवल मेंटेंनेंस उन मशीनों का नहीं हो पाया चूंकि जो बजट एलोकेट होता है और उसकी जो किश्तें विभिन्न अस्पतालों को जाती हैं वो टाईम से दी नहीं गयी, उन कंपनियों को एएमसी का पैसा दिया नहीं गया, मशीनों का एनुअल मेनटेनेंस हुआ नहीं, करोड़ों की मशीनें माननीय अध्यक्ष जी बंद पड़ी रही लगभग एक साल तक। लोगों को वो जांच जो फ्री में हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध हो सकती थी, सरकार के करोड़ों रूपये की मशीन इंस्टाल कराने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध कराने के बावजूद, फाईनेंस डिपार्टमेंट की अकर्मण्यता की वजह से और कुछ चुनिंदा चूंकि ज्यादातर अफसर काम करना चाहते हैं, कुछ चुनिंदा अफसरों के द्वारा एलजी के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर दिल्ली की सरकार के साथ, दिल्ली की जनता के साथ जो राजनीति की जा रही है इसकी वजह से वो पैसा समय से नहीं पहुंचा और एनुअल मेनटेनेंस नहीं हो पाई करोड़ों की मशीनें बंद पड़ी हैं। आज भी दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर पैट स्कैन मशीन नहीं चल रही है। ईहभास जो पूरे भारत के अंदर, वो लोग जिनको मानसिक बीमारियां हैं उसका इलाज कराता है वहां पे आज तक भी साल भर से फाईल लगातार घूम रही है आज तक भी एमआरआई की मशीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाइयों के लिये लोगों को जूझना पड़ा दवाइयां नहीं हैं और केवल इतना नहीं हुआ

बल्कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो जांचें होती थी मुफ्त में, उन जांचों को प्रभावित किया गया, रोका गया। बड़ी मुश्किल से लड़ लड़ के हमारे मंत्री जी अफसरों से किस किस तरीके से जूझते हुए उन समस्याओं का निदान किया है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका एक बात के लिये धन्यवाद करूंगा और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि पिछले दो तीन सत्र के दौरान इसी सदन के अंदर जब हमने इस मुद्दे को उठाया और मंत्री जी ने प्रोएक्टिव्ली काम किया, इससे एक तो फायदा हुआ है कि दवाइयों की समस्या तो अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई लेकिन वो मशीनों का मेनटेनेंस हो गया और मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया। इसके लिये मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा और उन अफसरों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने सहयोग देकर उन मशीनों को चालू कराया। लेकिन अभी भी दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीटयूट की पैटस्कैन मशीन चल नहीं रही है। अभी भी ईहभास के अंदर एमआरआई की फाईल लगातार घूम रही है उपर हैल्थ डिपार्टमेंट में, अभी तक भी वो मशीन उपलब्ध नहीं हुई है। ये जल्दी से जल्दी मिलना चाहिये और जिस तरह फरिश्ते योजना को लटकाया गया, यहां तक कि सारे वो मरीज जिनकी जान जा सकती थी, जिनकी जान बचाने का काम दिल्ली की सरकार ने फरिश्ता योजना के माध्यम से किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें पहल की और उस योजना को जिस तरह अफसरशाही ने बंद कर दिया था उसको भी लड़ लड़ के चालू करवाया। इससे एक बात तो स्पष्ट है सरकार की नीयत जनता के लिये काम करने की है, सरकार जिस तरह एजुकेशन के मामले में

गंभीर है उसी तरह हैल्थ के मामले में गंभीर है लेकिन इस अफसरशाही को राजनीति छोड़कर एलजी साहब के या केंद्र सरकार के हाथों में खेलने के बजाए क्योंकि वो जनता की नौकर है, एमएलए जनता के नौकर हैं, मंत्री जनता के नौकर हैं, आईएएस आफिसर जनता के नौकर हैं, मुख्यमंत्री, प्रधान मंत्री राष्ट्रपति सब जनता के नौकर हैं। कंस्टीट्यूशन कहता है they are public servants लेकिन वो मालिक बनने की कोशिश न करें, जनता के साथ खिलवाड़ न करें, इस तरह की राजनीति जनता के साथ ठीक नहीं है, ये रूकना चाहिये माननीय अध्यक्ष जी। बेहद गंभीर मामला है मतलब एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का और उस ऑर्डर में माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय का कंटेम्प्ट भी हुआ था कि किसी भी विभाग में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं कांट्रेक्ट पे करते हैं या आउट सॉर्स करते हैं उनको हर महीने की सात तारीख से पहले पहले सेलरी मिल जानी चाहिये लेकिन आउट सोर्स स्टाफ की कई बार छह छह महीने तक सेलरी नहीं मिलती जिसमें सफाई कर्मचारी, नर्सिंग ऑर्डरली और पियन का जो लोग काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड का जो लोग काम करते हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ जो कांट्रेक्ट पे काम कर रहे हैं और बहुत सारी डाक्टर जो कांट्रेक्ट पे काम कर हैं, उनकी सेलरी कई बार छह छह महीने तक नहीं मिलती है। मैं जानना चाहता हूं चीफ सेक्रेटरी कंटेम्प्ट झेलना चाहते हैं या ऐसे अधिकारियों को सजा देना चाहते हैं जिनकी वजह से उनके खिलाफ कंटेम्प्ट शुरू होने वाली है।

(समय की घंटी)

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः जिनकी वजह से समय से लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती है। सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा माननीय अध्यक्ष जी। लगभग सभी अस्पतालों में वैसे तो लगभग सभी विभागों की ये स्थिति है लेकिन अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां लोग इलाज के लिये आते हैं, वहां पर अभी भी डाक्टर्स की वैकेंसी खाली पड़ी हैं भारी मात्रा में, अभी भी पेरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग का स्टाफ, टैकनीशियंस, वो वैकेंसी खाली होने का मतलब है जो मशीनें चलाने का काम वो टेक्निकल एक्सपर्ट करता है अगर वो वैकेंसी भरी नहीं जाएगी तो वो मशीन चलेगी नहीं। इसकी वजह से लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा प्रयास और बढ़ाइये। हम लोग सब मिलकर उनके साथ रिक्वेस्ट करेंगे अधिकारियों से कि आप लोग जनता के सेवक हैं, हम लोग भी जनता के सेवक हैं इसलिए राजनीति बंद कीजिए और जल्दी से जल्दी सारा स्टाफ उपलब्ध कराइये। डीएसएसएसबी को गंभीर कीजिए ताकि वो टाइम्ली रिक्रूटमेंट का काम पूरा करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः राजेश गुप्ता जी।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, एक बहुत गंभीर मसला आपके संज्ञान में और हाउस के संज्ञान में लाना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा परिसर को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अखाड़ा बना रही है। अभी विधान सभा परिसर में भारतीय

जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष विधान सभा के अपोजिशन के जितने भी हमारे मेम्बर हैं उनके साथ मिलकरके गांधी जी की प्रतिमा के सामने न केवल प्रोटेस्ट कर रहे थे बल्कि मीडिया को bite दे रहे थे। ये विधान सभा परिसर चुने हुए विधायक यहां आकर दिल्ली की जनता के विषय के मुद्दों को उठाते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किसके साइन से अंदर आया और कैसे प्रोटेस्ट किया और मीडिया bite दिया, ये हम सबके प्रिविलेज का हनन है। तो मैं आपको लिखित शिकायत दे रहा हूं और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि ये हमारा, ये जो सदन के प्रिविलेज का हनन है और उस पर उचित कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष: दीजिए, आप राइटिंग में दीजिए। श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ता: माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद आपने एक बहुत गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आज दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे साथ आज इस सदन में नहीं हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है जो मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों की शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा पर जो काम करें, उन्हीं चीजों से घबराकर आज केंद्र की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल के पीछे भेजा। आज विषय जो आदरणीय राजेन्द्रपाल गौतम जी ने उठाया, वो स्पेसिफिक्ली चिकित्सा के बारे में है। पूरे भारत के अंदर दिल्ली ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने बजट का 13 परसेंट, मैं इस साल के ऊपर बता रहा हूं, सिर्फ हेल्थ के ऊपर खर्च करता है। और लगातार

जब से हमारी सरकार बनी है ये बजट 15 परसेंट, 16 परसेंट, 14 परसेंट, 13 परसेंट, इतना हमने रखा है। जब माननीय आतिशी जी ने ये बजट पेश किया तो उन्होंने बताया था कि 'राम राज्य की परिकल्पना' में जो दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत था या है वो ये है कि राज्य में कोई भी बीमार न रहे। आम भाषा में भी जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि 'पहला सुख निरोगी काया'। अगर घर में कोई फिट नहीं रहेगा तो कोई और काम वो नहीं कर सकता, न वो पूजा कर सकता, न वो बच्चों पर ध्यान दे सकता, न वो काम धंधा कर सकता, तो उसके शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली की चिकित्सा पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हुए दिल्ली में थ्री-टियर सिस्टम की व्यवस्था करी। एक हॉस्पिटल जो पहले भी थे लेकिन कितने गंदे थे, कितने खराब थे, हम सब जानते हैं कि पहले दिल्ली में एक आम बात कही जाती थी कि अगर आपको अपने रिश्तेदार को मारना है, मजाक करा जाता था, तो आप सरकारी अस्पताल में भेज दो, बड़ी संभावनाएं हैं कि वापस नहीं आएगा और साथ में जो उसका अटेंडेंट है वो भी किसी न किसी बीमारी में लग जाएगा। इतनी गंदगी, लिफ्ट थी नहीं, थी तो बहुत खराब थी, जगह-जगह गंदगी। शौचालय इतने बुरे हाल में, कोई जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था बनाई, उनके साथ में सत्येन्द्र जैन जी जो उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री थे, हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उसमें उनके साथ काम करने का, पार्लियामेंट सेक्रेटरी-हेल्थ बनने का और एक-एक हॉस्पिटल पर हमने निगरानी रखी। हमने हॉस्पिटल्स

को अच्छा बनाया। दूसरे टियर में हमने पॉली-क्लिनिक्स को लिया, जिसमें हमने ये कोशिश करी कि हर आदमी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है तो पॉली-क्लिनिक में जाकर वो अपने टेस्ट करा ले। और उससे भी नीचे बनाया गया मोहल्ला क्लिनिक को, कि एक मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक है अगर कोई बुजुर्ग जाना चाहता है, कोई महिला जाना चाहती है तो पैदल जाकर भी वो उस मोहल्ला क्लिनिक में जा सके, आने जाने का खर्चा भी बचे, टाइम भी बचे और साथ में पॉल्यूशन जैसी एक समस्या जो दिल्ली के पास होती है वो भी कम हो जाए, जब स्कूटर, गाड़ी कम चलेगी, वो पैदल ही चली जाएगी तो वो भी अच्छा होगा। इन्हीं बातों से घबराकर केंद्र की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी को तंग करने के लिए, दिल्ली की जनता को तंग करने के लिए उनको सलाखों के पीछे भेजा।

आज वो मोहल्ला क्लिनिक, जो एक छोटा सा एक मोहल्ला क्लिनिक होता क्या है, छोटा सा एक मोहल्ला क्लिनिक ही तो है, लेकिन वो इतना बड़ा मॉडल बन गया कि उसी की वजह से पंजाब में भी सरकार आ गई। वो इतनी बड़ी चीज बन गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब आए तो उनकी धर्म-पत्नी ने कहा भई मैं तो मोहल्ला क्लिनिक देखूंगी। बताओ कितनी, एक छोटी सी चीज बताते हैं ये, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा था, देश में, दुनिया में कि ऐसा क्या सिस्टम अरविंद केजरीवाल ने बनाया है जो दिल्ली की या देश की जनता को इतना फायदा दे रहा है। यूएन के महासचिव उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। घबराकर केंद्र सरकार ने एल.जी. साहब के माध्यम से ये कहा कि इस

सिस्टम को बदनाम करो, नहीं तो दिल्ली की जनता तो एक तरफ होती जा रही है। अभी दो महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री, सौरभ जी बैठे हुए हैं, इन्होंने एक मीटिंग ली उस मीटिंग पर हमको एक प्रोफॉर्मा दिया और कहा कि जाकर इसमें देखना है कि इनके शौचालय साफ हैं, नहीं हैं। बताइये, कौन ध्यान देता था शौचालयों के ऊपर, वो भी मंत्री, कोई मतलब ही नहीं था। और आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूं जब जाकर मैंने या मेरे बाकी विधायकों ने वो जाकर देखा तो हमारी उम्मीद से ज्यादा साफ थे वो। और मैंने सोचा कि क्योंकि मैं आया हूं तो इन्होंने पहले से साफ तो नहीं कर दिए तो पब्लिक से पूछा, उसकी विडियोस हैं मेरे पास में, तो जो लोग वहां पर थे, जो अटेंडेंट थे उन्होंने कहा नहीं जी ये बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं।

अब एक बात बताइये जो गौतम जी ने कहा मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। उनमें दवाइयों को रोक दिया जाए मोहल्ला क्लिनिक में, डॉक्टर्स के ऊपर केस बनाने की कोशिश हो क्योंकि इनको अपने डॉक्टर्स पर यकीन नहीं है, अरे इतना बच्चा पढ़ाई करता है तब डॉक्टर बनता है। आप कहते हो वो फेक अटेंडेंस लगाता था, आपने केस डाल दिया। क्या इस देश के डॉक्टर पर भाजपा की केंद्र की सरकार को यकीन नहीं है, क्या वो धोखेबाज हैं डॉक्टर्स जो इतनी पढ़ाई लिखाई करके आए हैं? नहीं, उनके ऊपर केस करा। दवाइयां रोक दी गई, टेस्ट रोक दिए गए।

अरे दीपचंद बंधु जैसे अस्पताल से, वजीरपुर विधान सभा में जहां से मैं विधायक होकर आता हूं, सर कुछ भी नहीं था, एक सर्विस चालू नहीं थी। दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी बार-बार झगड़ा करती थी नारियल फोड़ने के नाम का। जब मैं वहां विधायक बना, मुख्यमंत्री जी से बात करी, एक-एक सर्विस चालू करी और मैंने सत्येन्द्र जैन जी से कहा कि सर लोग कह रहे हैं कि मुहूर्त कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा समय नहीं है यार मुहूर्त करने का, तो सब कुछ चालू करे जाओ और आज तक ये ही हो रहा है, कोई मुहूर्त मुझे याद नहीं आता मैंने करा हो लेकिन सारी सर्विसेज चालू कर दी। आज जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे, जच्चा-बच्चा केंद्र में दूर-दूर से लोग उस हॉस्पिटल में आते हैं कि नहीं भई ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बेमतलब के टेस्ट नहीं करते, बेमतलब के ऑपरेशन नहीं करते, एक अच्छा इलाज करते हैं।

आज जिन सर्विसेज को रोकने की कोशिश जिस हेल्थ सेक्रेटरी ने करी, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कैसे उन्होंने रोका, कौन जिम्मेवार है? जब मंत्री कह रहे हैं कि हॉस्पिटल अच्छा चलना चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, विधायक कह रहे हैं, एमएस कह रहा है, तो कौन है उस दवाइयों के लिए जिम्मेवार?.. हमारे मंत्री जाकर थोडही़ एक एक कागज देखेंगे कितनी एक्सपायरी दवाई है, कौन अच्छी आ रही है, कौन बुरी आ रही है, कौन जिम्मेवार है उसके लिए, अगर टेस्ट रोके जा रहे हैं, कौन जिम्मेवार है उसके लिए?

ये लोग जो दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं, दिल्ली छोटी सी है अध्यक्ष जी। अगर जीटीबी हॉस्पिटल में जाएं न तो सबके सब लोग यूपी से यहां आते हैं। बेमतलब शोर मचाते हैं 'आयुष्मान भारत योजना', अगर इतनी अच्छी है तो ये लोग आते क्यूं? मैं चैलेंज करता हूं मीडिया के साथियों से, मेरे साथ चलें, मैं दिखाता हूं आपको जीटीबी के अंदर कि कहां के लोग ज्यादा हैं। मैं चैलेंज करता हूं एलएनजेपी में चलें मेरे साथ में, मैं दिखाता हूं कि दिल्ली के लोग भी हैं और बाहर के कितने लोग वहां पर आ रहे हैं। जितने भी peripheral hospitals हैं, आप चलिए नरेला में, आपको दिखेंगे कि हरियाणा की तरफ से लोग आ रहे होंगे सोनीपत से। आप चलिए नजफगढ़ में तो आपको बहादुरगढ़ की तरफ के लोग दिखाई देंगे। अरे भई देश सबका है, हम सबको आने देते हैं, अच्छी बात है, दिल्ली में एक अच्छी व्यवस्था है। लेकिन आप न सिर्फ दिल्ली की जनता के साथ में बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा की जनता, वहां तो आप इलाज कर नहीं रहें, अरे हम यहां पर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत है।

ये जो षड़यंत्र रचा गया है सरकार को बदनाम करना, देखिए मैं, एक बाहुबली पिक्चर आई थी अध्यक्ष जी, उसमें दोनों राजकुमार भागते हैं, एक विलेन से झगड़ा करने के लिए जो उनके देश पर आक्रमण करता है। पहला वाला राजकुमार ये भी नहीं देखता कि अपने लोग हैं वो उन्हें भी मार देता है क्योंकि उसे गद्दी चाहिए थी, सीट चाहिए थी, कहता है मार दो, अपने भी मर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे तो ये दिखाना है कि भई मैं बहुत शक्तिशाली हूं। लेकिन दूसरा रूक

जाता है, कहता है नहीं मेरे लोग हैं, मैं इन्हें नहीं मारूंगा, ऐसी गद्दी का क्या करना जहां अपने ही मारे जाए। मुझे लगता है वो पिक्चर भाजपा के एक-एक कार्यकर्ता को, एक-एक मंत्री को और प्रधानमंत्री जी को जरूर देखनी चाहिए कि ऐसी गद्दी का क्या फायदा कि तुम्हारे लोगों को ही नुकसान हो जाए, क्या करोगे ऐसी सत्ता को लेकर। अरे झगड़ा करना है मुख्यमंत्री जी से करो। हमने दस मोहल्ला क्लिनिक एक-एक विधान सभा में बनाए, आप उत्तर प्रदेश में बना लो बारह, आपके पास तो बहुत पैसा है, बनाओ। आपके पास इलेक्टोरल बांड से बहुत पैसा आया है, लगा दो उस पैसे को। ये कौन सा तरीका हुआ जो आदमी काम कर रहा है उसको उठाकर आप बंद करोगे?

तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय राजेन्द्रपाल गौतम जी ने जो बात रखी है कि हमारे अस्पतालों में, पॉली क्लिनिक्स में और हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स में जो सर्विसेज जो पूरी दुनिया में जानी जाती थी उनको रोकने का षड्यंत्र जिसने भी करा है, जो भी अधिकारी उसके अंदर सम्मिलित हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और इस विधान सभा को वो जरूर जवाब दें कि उनमें जो भी कमी है वो किसकी वजह से हुई, कौन उसका जिम्मेवार है। आपने मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने इस, जो दिल्ली में लगातार चीफ सेक्रेटरी और अधिकारियों के कारण

हेल्थ व्यवस्था चरमरा रही है उस पर हाउस में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे साथी विस्तार से इसकी चर्चा कर चुके हैं और ये चिंता लगातार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जाहिर भी कर चुके हैं अपने पत्र के जरिए एल.जी. साहब को, चीफ सेक्रेटरी को लेकिन उसमें कोई ठोस शुरूआत नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ये चीफ सेक्रेटरी या एल.जी. साहब ये ठान लिए हैं कि दिल्ली के लोगों की जो स्वास्थ्य की सुविधा दिल्ली सरकार से मिल रही थी उसको खत्म कर देना है। अब ये क्यूं ठान लिए हैं ये तो हमें नहीं पता। मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर मानवता होती है। राजनीति करो लेकिन राजनीति विनाश का न करो। अगर कोई व्यक्ति आपके गलत इंटेंशन के कारण उसका इलाज नहीं हो पा रहा, उसको दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं तो मुझे लगता है इससे ऊपर वाले भी खुश नहीं होंगे। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से बात कर रहा था, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा मैं लगातार चिट्ठी लिखता रहा हूं और मुझे हेल्थ सेक्रेटरी भी और चीफ सेक्रेटरी ने भी ये आश्वासन दिया कि दवाइयों की कोई कमी नहीं हैं।

मैं अपने, मेरे यहां बुराड़ी अस्पताल है और बुराड़ी अस्पताल में मैंने कुछ पेशेंटों से आज बातचीत करी कि आप जो आज गए हैं वहां पर तो क्या आपको सारी दवाइयां मिली। चार मेरे पास जो वहां पर स्लिप हॉस्पिटल की मिलती है वो मुझे मिला और मुझे भेजा। एक पेशेंट को तीन दवाइयां लिखी गई, तीन में से दो नहीं हैं, दो नहीं मिला केवल एक मिला। दूसरे पेशेंट को,.. दीपक कुमार, पेशेंट का नाम है और रूम नंबर 112 में ओपीडी में दिखाने के लिए गया था उसमें कोई, अब

डॉक्टर का पढ़ा हुआ दवा का नाम पढ़ना बहुत मुश्किल है, मैं ये संज्ञान में दे दूंगा सारा... सारा रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगा। तो एक दीपक कुमार का है, एक कोई पुष्कर कुमार का मेरे पास है इसको लिखा गया, पांच दवा लिखा गया, जिसमें से दो नहीं मिला, तीन दवा मिला।.

...व्यवधान...

श्री संजीव झा: ये बुराड़ी हॉस्पिटल का है...

...व्यवधान...

श्री संजीव झा: आज का है ये। एक कोई पेशेंट हैं मोनू, जिसको चार दवा लिखा गया था, दो मिला और दो दवा नहीं मिला। इसी तरह से एक कोई पेशेंट है उसको नौ दवा लिखा गया उसमें से चार मेडिसिन उसको नहीं मिला, पांच मेडिसिन उसको मिला। तो ये आज की हालात है और मैंने और भी पेशेंट्स से पुछवाने की कोशिश करी, उन्होंने कहा कमोबेश पिछले से महीनों से ये चल रहा है कि मेडिसिन की भारी कमी है।

एक बात समझिये, आजादी के 77-78 साल हो गए, बाबा साहेब ने संविधान में लिखा था कि स्वास्थ्य की और शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। इस 75 साल में किसी भी सरकारों ने हरेक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए इस पर काम नहीं किया। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है जिस पार्टी का मैं हिस्सा हूं वो देश में पहली ऐसी सरकार थी जो ये एनश्योर किया कि चाहे आप कितने भी गरीब क्यूं न हो, आपको दवाई, जांच, इलाज और गुणवत्तापूर्ण

ये आपको मुफ्त मिलेगा। मुझे लगा चलो आजादी के 75 साल बाद ही सही बाबा साहेब की आत्मा को शांति मिल रही होगी, कोई सरकार तो आया जो मेरे सपनों पर काम कर रहा है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। खुद तो तुम करोगे नहीं और जो सरकार कर रही है उसके काम को रोकोगे। आज दिल्ली में चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, गरीब से गरीब आदमी जाता है उसकी सभी जांच, दवाइयां, इलाज सब मुफ्त होता है। यहां तक कि प्राइमरी टेस्ट तो छोड़ दीजिए अगर किसी को महंगे टेस्ट भी कराना हो तो वो मोहल्ला क्लिनिक में लिख दिया जाता था और आप किसी भी प्राइवेट लैब में जांच करा लीजिए, आपको एक रुपया नहीं लगेगा। सरकारी अस्पताल में अगर आप जाते हैं अगर मान लीजिए कोई भारी बीमारी है, कोई ऑपरेशन करना है और वहां पर समय लग रहा है तो वहां से एक DAK में लिख दिया जाता था, आप प्राइवेट जाकर करा लीजिए, आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। एल.जी. साहब ने और अधिकारियों ने वो जो प्राइवेट अस्पताल के बिल थे उसको देना बंद कर दिया, जो प्राइवेट लैब में जांच हुआ उसके बिल को देना बंद कर दिया, क्या मंशा थी उनकी? ये मंशा तो नहीं थी न चीजें ठीक हो जाए। मंशा ये थी कि गरीब को अब प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं हो, गरीब कैसे प्राइवेट में इलाज करा सकता है, वो कपड़े साफ नहीं हैं उनके। कोई गरीब का प्राइवेट लैब में उसका टेस्ट न हो पाए, वो ऐसे ही सरकारी अस्पताल में धक्के खाते रहें और मरते रहें।

मुझे लगता है कि राजनीति इतनी नीचता पर ले जाना, इतना राजनैतिक नीच हो जाना, इस तरह से आप किसी सरकार से बदला लेते-लेते गरीबों से बदला लेना, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, मानवता नहीं है। मैं ये चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी को भी कहना चाहता हूं कि माना आप नौकरी करते हैं और आपकी मजबूरियां हैं कि आपको नौकरी करना है पर आप इंसान तो हैं। देखिए इस लोकतंत्र की तीन अंग थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, जरूरी नहीं है, एग्जीक्यूटिव की अपनी जिम्मेदारी है और सब एक दूसरे से, एक फाइन लाइन है इंडिपेंडेंट होने का कि कभी अगर मान लीजिए कोई गलत काम कराया जा रहा है तो नौकरी कर रहे हैं ये करना ये जरूरी नहीं है। आपको इस कॉन्स्टिटयूशन ने और डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको ये अधिकार दिया है कि गलत को विरोध करें। मुझे लगता है कि जब आप नौकरी में आए होंगे तो ये सपना लेकर शायद आए होंगे कि हम देश का सेवा करेंगे, लोगों का सेवा करेंगे और अगर आपके एक सिग्नेचर या आपके एक चिट्ठी नहीं होने के कारण अगर किसी गरीब का इलाज नहीं हो रहा है तो ये एक तरह से देशद्रोह है। ये एक तरह से आप इस देश के नागरिक के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं एल.जी. साहब को भी कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि आप किसी के रहमोकरम पर आप एल.जी. हैं, लेकिन इंसान तो हैं न आप, इंसान हैं तो एल.जी. हैं, इंसान नहीं होते तो एल.जी. नहीं होते। तो कम से कम जहां बात इंसानियत की आ जाए वहां ऑर्डर लेना बंद कर दीजिए चूंकि ये सारी बातें दर्ज हो रही है। कभी तो

इतिहास में चर्चा होगी। आज भी हम इतिहास बहुत लोगों को पढ़ते हैं कि कौन लोग इस देश के साथ खड़े थे, कौन इस देश के साथ नहीं खड़ा था, कौन देश के मुद्दों के ठीक करने के साथ खड़ा था, कौन देश के मुद्दों के खिलाफ खड़ा था। आज के बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, कई बार समकालीन नहीं समझ पाते हैं कि आप क्या न्याय और अन्याय किए हैं, ये सारा हिसाब-किताब इतिहास में दर्ज होता है और इतिहास ये तय करता है कि गद्दार कौन था और देशभक्त कौन था। कई बार अंग्रेज के साथ काम करने वाले लोग अंग्रेज के साथ खड़े रहे होंगे, हो सकता है कि उनको उसमें कंर्ट मिला होगा, हो सकता है कि उनको वो सारी सुख-सुविधाएं मिली होगी लेकिन आज हम उसको गद्दार कहते हैं। भगत सिंह जंगल में जब मीटिंग कर रहे होंगे, जंगल में जब रह रहें होंगे तो हो सकता है उनको कष्ट हो रहा होगा लेकिन आज उनको हम 'शहीदे आजम भगत सिंह' कहते हैं। तो ये इतिहास तय करेगा कि आप इस देश के गद्दारों की लिस्ट में हैं या इस देश के लोगों की सेवा करने की लिस्ट में हैं।

इस सरकार से लोगों की उम्मीदें हैं, इस सरकार से लोगों की उम्मीदें हैं इसीलिए जैसा मैंने पहले कहा कि पहली बार किसी गरीब को भी वही इलाज मिल रहा था जो अमीरों को मिल रहा था, आपने उस पर भी संकट ला दिया। पहले आपने, जिसने इस हेल्थ मॉडल को revamp किया जिस मंत्री ने पहले उसको जेल में भेज दिया आपने, उसके बाद जो लोग, दूसरी मंत्री काम कर रहे हैं फिर उसको आप ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये तो अन्याय है तो लोकतंत्र तो खत्म

हो गया, कहां है लोकतंत्र फिर? लोकतंत्र में अगर मिनिस्टर के ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव नहीं फॉलो करेगा तो फिर तो सारा लोकतंत्र का तानाबाना ही खत्म हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी लेकिन अगर आप ये समझते हों कि आप फाइल पर जो भी अनाप-शनाप लिख रहे हैं, आप जिस तरह से आप फाइल के साथ खिलवाड़ कर रहे हों, कल आपके कैरियर से खिलवाड़ न हो ये ध्यान रखना आप। ये सरकारें पांच साल के लिए आती है, सरकारें पांच साल के लिए जाती है लेकिन आप जो फाइल पर लिखते हो वो हमेशा के लिए लिखी जाती है। आप अपनी जिम्मेदारी को अगर ठीक से नहीं समझ पा रहे हो जो आपको constitution ने दिया है तो फिर उसका नुकसान और फिर उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि आज जिस तरह से सरकारी अस्पताल हो या मोहल्ला क्लीनिक हो, मोहल्ला क्लीनिक कोई ये जांच के लिए कभी कोई सीबीआई की जांच, कभी किसकी जांच, कभी किसकी जांच अब उस जांच के डर से ना तो वहां कोई डॉक्टर आता है, ना तो कोई वहां लैब टैक्निशियन पे बैठना चाहता है। जो मोहल्ला क्लीनिक चल रहा था वहां से डॉक्टर छोड़के चला गया। क्या मंशा है आपकी? ये आप सरकार से बदला ले रहे हो? ये सरकार से बदला नहीं ले रहे आप, ये बदला आप दिल्ली के गरीब जनता से ले रहे हो। अरे इसी गरीब जनता ने आपको भी लोकसभा में वोट किया था, लेकिन आज मैं इस सदन के माध्यम से अपने दिल्ली की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि अब ये समय कौन जीतेगा

कौन हारेगा उससे बड़ा विषय है कि इस देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा, इस देश का संविधान कैसे बचेगा चूंकि जिसको जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है और जिसको केन्द्र में रक्षा की जिम्मेदारी के लिए आपने चुना वो उसका दुरूपयोग कर रहा है। तो अब ये वक्त आ गया है कि अगर अब नहीं बोले और अभी अगर निर्णय नहीं लिया तो हो सकता है कि दोबारा निर्णय लेने के लायक भी ये ना छोड़ें। तो जनतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं।

(समय की घंटी)

श्री संजीव झाः एक-एक घर जाकर के ये बताना पड़ेगा कि किस तरह से मोहल्ला क्लीनिक को बर्बाद करके देश दिल्ली के गरीबों से बदला ले रहे हैं ये। आज दिल्ली के अस्पतालों में दवाई नहीं पहुंचा करके गरीबों का इलाज ठीक से ना हो ये सुनिश्चित करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है और केंद्र सरकार के जरिये एलजी और उनके ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं। तो दो ही बात कहके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। पहली बात कि ये जो अधिकारी फाइलों पर खेल खेल रहे हैं ये खेल खेलना बंद करें और दूसरी बात कि अगर आप हमसे राजनीतिक बदला लेना चाह रहे हो तो हमसे लो लेकिन दिल्ली की गरीब जनता से बदला ना लो। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में और जैसा अब मंत्री जी ने कहा है कि उनको ब्रीफ किया गया है कि हैल्थ सेकेट्री, चीफ सेकेट्री ने आके इन्श्योर किया है कि मेडिसिन सब जगह ठीक है अगर नहीं हैं तो ये सदन आगे उचित

कार्रवाई करे, ताकि ये अधिकारी राजनीति जो फाइलों पर कर रहे हैं उससे वो बचें और सबक लें। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः श्री राजेश ऋषि जी। बहुत संक्षेप में राजेश जी प्लीज।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष जी बहुत छोटे में बोलूंगा मैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियम 54 के अंतर्गत राजेन्द्र पाल गौतम जी जो लेकर आये हैं। मैं उसी पे आगे बताना चाहता हूँ कि सर ये स्थिति जो आज अस्पतालों की हुई है उसके बारे में अभी हमारे संजीव झा जी ने पूरे तरीके से बताया है कि किस तरीके से हमारे एलजी साहब कर रहे हैं। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अरविन्द केजरीवाल जी ने जब सरकार पहली बार बनी उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए बहुत बड़ा काम किया। अभी जैसे राजेश गुप्ता जी ने बताया कि पार्लियामेंट्री सेकेट्री बनाये गये, मुझे भी बनाया गया था पार्लियामेंट्री सेकेट्री। उसके बाद हम लोग पूरी तौर से हम लोग लगे सारी जगह। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि सर हमारे यहां पर एक अपोलो हॉस्पिटल है। इस अपोलो हॉस्पिटल के अंदर दिल्ली सरकार के 225 बैड हैं ईडब्लुएस में और लगभग 34 बैड की आईसीयू है। जब हमारी सरकार बनी थी जब हम उसे देखने गए तो हम देख के हैरान थे कि वहां 65 बैड का ही प्रयोग हो रहा था बाकि वो हॉस्पिटल खुद यूज करता था। अरविन्द केजरीवाल सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि पूरे बैड यूज होने लगे और वेटिंग लिस्ट बन गई वहां पर। आज क्या स्थिति है हम नहीं जानते इसके बारे में लेकिन

उस समय ये स्थिति थी। हमारे फॉर्टिस में भी हैं बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में हमारे काफी सारे बैड हैं लेकिन जो व्यवस्था आज चल रही है, धीरे-धीरे बिगड़ती चली जा रही है। हम देख के हैरान हैं। अभी राजेन्द्र पाल गौतम जी ने बताया कि हमारे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी होस्पिटल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया और well equipped है। साथ ही उसके केंसर इंस्टीट्यूट है जिसकी एक ब्रांच मेरे जनकपुरी में भी है और ये जब हम बनें पार्लियामेंट्री सेकेट्री तो हमने सारे हॉस्पिटल्स में दौरा किया। जब राजीव गांधी इंस्टीटयूट गए हम क्योंकि हमें मौका मिला था अपने हैल्थ चैकअप का भी, हम देख के हैरान थे कि इतने शानदार हॉस्पिटल हमारे दिल्ली के अंदर हैं जिनमें इतने शानदार डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन दिन-ब-दिन स्थिति बिगड़ती चली जा रही है क्योंकि पावर्स जो हैं वो एलजी के पास ट्रांसफर हो गई और जितनी भी ओटोनोमस बॉडीज हैं इसमें चेयरमेन नहीं होते एमएलए, इसमें चेयरमेन या तो स्वास्थ मंत्री होते हैं या फिर एलजी साहब। तो पूरा का पूरा ढांचा उन्हीं के हाथ में होता है और वो ही हैं जो चाहते हैं अपनी मनमानी से करते हैं। मेरे यहां भी एक ओटोनोमस बॉडी का हॉस्पिटल है जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वो भी बहुत ही शानदार बना हुआ है। लेकिन दिल्ली सरकार बनने के बाद जैसे ही अरविन्द केजरीवाल सरकार बनी उसके बाद इस हॉस्पिटल की कायापलट हो गई। पहले लोग उसे कहा करते थे ये स्फेद हाथी खड़ा है, कब चलेगा। सफेद हाथी खड़ा है कब चलेगा। लेकिन जब चलना शुरू हुआ तो आज ऐसा लगता है आप बाहर खड़े हो जायें तो लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसके

सामने फेल है। लेकिन उसके अंदर सुविधायें बहुत हैं। सारा इलाज फी हो रहा है। सब दवाइयां फी मिल रही हैं लेकिन आज स्थिति थोड़ी बिगड़ती जा रही है। स्थिति ये हो गई है कि वहां पर अब दवाइयां धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। मैं उस दिन जाके उनके एमएस से मिला तो उन्होंने बताया कि सर दवाइयां आ नहीं रहीं। बहुत सारी दवाइयां खरीद ही नहीं रहे। जो महंगी दवाइयां वो मिल नहीं रहीं। पेसेंट बेचारे घूम रहे हैं। हम जहां तक हो सकता है हम करके देते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। सर जब अरविन्द केजरीवाल सरकार बनी उस समय जब हम पार्लियामेंट्री सेकेट्री हैल्थ थे हमारे पास लोग आते थे कि हमारे को डायलेसिस नहीं हो पा रहा और हम खुद देखते थे कि बेचारा गरीब आदमी डायलेसिस नहीं करा पाता था पैसे तो बेचारा दो महीने, चार महीने, छः महीने बाद उस दुनिया से चला जाता था। लेकिन अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार की मेहरबानी से हमारे जनकपुरी के अंदर डायलेसिस की सुविधा शुरू हुई। ये डायलेसिस हमारे यहां लगभग 60 बेड तक इसको एक्सटेंड करने का कार्यक्रम है। अभी लगभग 30 बेड पे चल रहा है। तो गरीब आदमी जो बेचारा बिना इलाज के चला जाता था इस दुनिया से अरविन्द केजरीवाल सरकार के कारण आज कम से कम उसकी जिन्दगी लम्बी हुई है और वो दुआयें देता है कि हाँ सारा कुछ बढ़िया से चल रहा है। लेकिन दुख की बात ये है कि यहां पर जो इंजेक्शन लगता है एक इसमें जो डायलेसिस वालों को वो बहुत महंगा इंजेक्शन है वो मिल नहीं पाता क्योंकि डॉक्टर्स रेुर करते हैं, डॉक्टर ही मंगाते हैं, डॉक्टर ही लगाते हैं। हमारे हॉस्पिटल के अंदर सारे

के सारे इंजेक्शन पी लगते थे। लेकिन आज इंजेक्शन की परचेज नहीं हो रही ये दिक्कत है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मनीष सिसोदिया जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे उनके समय में मैंने दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट जो जनकपुरी वाला है उसकी बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है। जब वहां डायरेक्टर थे राजेश ग्रोवर जी तब ये अस्पताल ऐसे लगता था जैसे प्राइवेट से भी बहुत सुंदर चल रहा है और सारी सुविधायें थीं और उनका भी सपना था कि दिल्ली के अंदर चार हॉस्पिटल ऐसे बनायें जायें ताकि वहां पर इलाज लोगों का बढ़िया से बढ़िया हो सके क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों के मकान बिक जाते हैं, ज्वैलरी बिक जाती है, लेकिन वो बचा नहीं पाते लोगों को। लेकिन अरविन्द केजरीवाल जी ने ऐसी व्यवस्था बनाके दी कि गरीब आदमी का ना तो कभी मकान बिकेगा, ना कभी उसकी ज्वैलरी बिकेगी और उसका बढ़िया से बढ़िया इलाज होगा। मेरे यहां पर कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर करोड़ों रूपए की मशीनें खड़ी हैं। ये मशीनें लगभग आज छः साल हो गए। 14, 15 करोड़ की मशीन लीनर एस्सीलेटर आई थी जो आज तक खड़ी है। चल नहीं पा रही।

माननीय अध्यक्षः ऋषि जी कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री राजेश ऋषिः बस दो मिनट बस सर। ये मशीन चलाने के चलते हमने दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट को जो ब्रांच जनकपुरी की है उसको जनकपुरी सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल में ट्रांसफर के लिए एक साल पहले दिया था। लेकिन आज तक उसके ऊपर कार्रवाई होते होते अभी तक रूकी हुई है। जैसे ही ये ट्रांसफर हो जायेगा जनकपुरी सुपरस्पेशलिटी

हॉस्पिटल में क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स हैं जो उस मशीन को चला सकते हैं उनको चलाया जाये लेकिन वो हो नहीं पा रहा। दवाइयों का धीरे-धीरे कमी आ रही है। मैं आपसे ये ही अनुरोध करूंगा कि ये जो व्यवस्था बनी हुई है और जो हमारे सीपीए द्वारा जो दवाइयां रोक दी जाती हैं, नहीं खरीदी जातीं, इनको दोबारा चालू कराया जाये और एक छोटी-सी बात और रखना चाहूंगा। एक हमारे इस कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर सर्वाइकल कैंसर के हमारे इंजेक्शन्स लगते थे बच्चियों को फ्री जोकि बहुत सालों, लगभग डेढ़ साल से लगना बंद हो चुके हैं क्योंकि वो दवाइयां परचेज नहीं हो रही। लेकिन जानकारी मुझे मिली थी कि दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट जो दिलशाद गार्डन में है वहां पर ये इंजेक्शन पड़े-पड़े खराब हो गए, लगाये नहीं गए। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी बैठे हैं इसकी जांच करें ये खराब क्यों हुए और बच्चियों को क्यों नहीं लगाये गए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान शिवचरण गोयल जी।

श्री शिवचरण गोयलः अध्यक्ष जी आपने मुझे राजेन्द्र पाल गौतम जी द्वारा मोहल्ला क्लीनिक की कमियों के बारे में मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी जिस तरह 2015 में सरकार बनी। उस समय दिल्ली की स्थिति जैसे पूरे देश में है इसी तरह से दिल्ली में भी स्थिति हर चीज की खराब थी। चाहे वो पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, बस, तो व्यवस्था सारी बिगड़ी हुई थी क्योंकि देश में सरकारें इसी तरह से काम करती थीं। माननीय मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी जो आंदोलन से

निकले हुए नेता हैं और इन्होंने दर-दर जाकर आंदोलन किये थे, हर एक की रग पहचानी थी। जब मुख्यमंत्री बने, जब 49 दिन की पहले सरकार बनी 2013 में तो मुझे याद है कि सरकारी अफसर्स ने रिश्वत लेनी बंद कर दी थी। सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस वाले हाथ जोड़ देते थे कि सर पैसे नहीं चाहिए आप मेरी विडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ये डर था कि सरकार अब भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन जब 2015 में सरकार बनी तो मई 2015 में एंटी करप्शन ब्यूरो ले ली गई और कहीं ना कहीं उनके मंसूबे जो थे उसी समय ही ये दर्शा दिये गए थे कि हम दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी एलजी के इंटरफेंस के बाद भी दिल्ली सरकार हर काम करती गई। मुझे याद आ रहा है जब सीसीटीवी के लिए हम आंदोलन करने निकले सड़क पर तो मुख्यमंत्री इनको लीड कर रहे थे। एलजी हाउस के बाहर 12 बजे हम पहुंचे और जून का महीना था। सारे विधायक मंत्री नंगी सड़क पर हम सब बैठे हुए थे और पसीने से तर ब तर थे और हमारी डिमांड ये ही थी एलजी साहब से कि हमारे सीसीटीवी कैमरे पास कर दिये जायें, फाइलों को पास कर दिया जाए, लेकिन फिर भी नहीं हुई। फिर एलजी हाउस में जाकर सारे मंत्री गोपाल जी, सत्येंद्र जैन जी, मनीष जी अरे मुख्यमंत्री खुद चारों सदस्यों ने वहां पर डेरा लगाया और दस दिन तक वहां पर अनशन किया तब जाकर वो फाइल पास हुई। इन्हें पता है ये जो अरविन्द केजरीवाल है ये जैसे मर्जी काम करवाये करवायेगा और ये रूकने वाला नहीं है और सारे काम हुए, सारे परिवर्तन हुए। क्या स्कूल था, हॉस्पिटल था, बस थी सभी परिवर्तन हुए

और 11 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली सरकार को पूरा हक है सरकार चलाने का उसमें किसी का भी इंटरफेस नहीं किया जा सकता। लेकिन 10 दिन बाद जिस तरह से सेंट्रल गवर्मेंट ये काला अध्यादेश लेके आई और दिल्ली की सारी शक्तियां एलजी साहब को ट्रांसफर हो गईं। उसके बाद ये षड़यंत्र शुरू हुआ दिल्ली सरकार को गिराने का। जब इलेक्शन आया एमसीडी का मेरे यहां पर एक मोहल्ला क्लीनिक है शिवानंद बस्ती और वो बस्ती में कम से कम भी 5 हजार लोग रहते हैं। उस डॉक्टर की सैलरी बंद कर दी। डॉक्टर की सैलरी नहीं आई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तो डॉक्टर रिजाइन करके चली गई। उनके टैस्ट रोक दिये गए। उनके जितने भी अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे सब बंद कर दिये गए और वो मोहल्ला क्लीनिक 4 महीने बंद रहा। शिवानंद बस्ती पंजाबी बाग के अंदर। इसी तरह से आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल जो 2015 से पहले गंदगी का ढेर था। पेसेंट जाते नहीं थे। जब मुझे चेयरमेन बनाया गया उसका और जब मैं पहली बार गया उसकी दशा और दिशा क्या थी ये आप मोती नगर की जनता से पूछ सकते हैं और आज वो दिल्ली का नंबर वन हॉस्पिटल है। 2017 में भी उसको अवॉर्ड मिला था कायाकल्प का और 2023 में भी उसको अवॉर्ड मिला कायाकल्प का 15 लाख रूपए की सम्मान राशि भी मिली। उस हॉस्पिटल में या पूरी दिल्ली के हॉस्पिटल में रातों-रात डाटा ऑपरेटर हटा दिये गए। 4 हजार पेसेंट वहां डेली ओपीडी में आता है। लम्बी-लम्बी लाइनें लग गयीं। ये क्या दर्शा रहा है आप दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से षड़यंत्र रचा जा रहा है कि

किसी भी तरह से सारी व्यवस्थाओं को खराब किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री हमारे स्वास्थ्य मंत्री हमारे यहां 4 महीने पहले सौरभ भारद्वाज जी आये थे और बकायदा जहां से मेडिसन डिस्टीब्यूट होती है सुबह आये थे करीब 11 बजे और शाम के 5 बजे गए हैं। पूरा एक-एक डाटा ले के गए। तो हमारा मकसद एक ही था कि दिल्ली की जनता को चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे 24 घंटे बिजली हो वो उपलब्ध करवाया जाए। लेकिन अब इलैक्शन आ गए हैं सेंटर के तो सेंटर के इलैक्शन को देखते हुए ये सारी सुविधाओं को बंद कर रहे हैं। और दोबारा से वो ही षड़्यंत्र शुरू कर दिया जोकि एमसीडी के इलैक्शन से पहले था। संजीव जी ने भी पूरी बात बतायी तो मैं तो ये ही कहूंगा मेरे गुरू जी एक बात कहा करते थे और आज मैं सभी से कहता हूँ वो कहा करते जो राजा बनता है जिसके पास पावर होती है वो राजा होता है लेकिन अगले जन्म में ज्यादातर वो भिखारी बनता है। मैंने पूछा अपने गुरू जी से मैंने कहा ये भिखारी क्यों बनता है। कहता है ज्यादातर राजा उन कामों को नहीं करता जिसके लिए उसको प्रभु ने भेजा है। तो अगली बारी कहां रहेगा उसके कर्म उसको डिसाइड करेंगे कि अगली योनी में वो कहां जायेगा। तो ये जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं जो भी तानाशाही कर रहे हैं वो ये जान लें कर्मों का खेल है, पलट के दोबारा आता है। आज जिसे तु रूलायेगा, कल कोई और तुझको रूलायेगा। समय नजदीक है अभी भी यदि वो अपने आप को ये समझ लें कि मुझे धरती पर भगवान श्री कृष्ण जो गीता में बोल के गए हैं उन कर्मों के आधार पे चलेंगे तो

आगे रस्ता नेकी का तैयार है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। राखी बिड़लान जी।

श्रीमती राखी बिरलाः धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे इस वक्त दिल्ली की चरमरायी हुई स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलने का मौका दिया। अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले मैं एक लाइन क्लीयर कर दूं कि यहां पर जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो सरकार द्वारा नहीं अधिकारियों द्वारा और एलजी द्वारा जो कुकर्म किये जा रहे हैं उसकी वजह से स्वास्थ्य सेवायें चरमरायी हुई हैं क्योंकि छोटे-छोटे यू-ट्यूबर्स, छोटे-छोटे न्यूज चैनल फिर इसको एडिट करके ऐसे चलाते हैं कि विधायक अपनी ही सरकार की बुराई कर रहे हैं। अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं पर वो सवाल उठा रहे हैं। अध्यक्ष जी मुझसे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी चर्चा रखी, बात रखी और अमूमन हर एक विधायक के विधान सभा क्षेत्र में सरकारी अस्पताल है दिल्ली सरकार का बड़ा होगा, छोटा होगा, मोहल्ला क्लीनिक होगा, डिस्पेंसरी होगा और सबने अमूमन दवाइयों की कमी के बारे में बताया होगा, स्टाफ की कमी के बारे में चर्चा करी यहां तक कि किस प्रकार से व्यवहार जनता के साथ, गरीब पेसेंट्स के साथ किया जाता है हर एक साथी विधायक ने बात रखी। अमूमन अचानक से तो ये घटना घटी नहीं होगी अध्यक्ष जी। क्योंकि साल 2013 से पहले की जब हम बात करें जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में हम लोग चुनकर आये और पहली बार जब चुनकर आये तो मेरे खुद के क्षेत्र में संजय

गांधी अस्पताल है दिल्ली सरकार का और इन सरकारी अस्पतालों के बारे में एक आम राय ये थी कि अगर कोई मरीज अपना इलाज इन अस्पतालों में कराने के लिए जायेगा तो वो सकुशल वापस नहीं लौट सकता, वो चार कंधों पर ही वापस लौटेगा। लेकिन साल 2013 के बाद जिस प्रकार से अभूतपूर्व परिवर्तन हम लोगों ने सरकारी अस्पतालों में देखे या यूं कहें कि दिल्ली के हर एक सरकारी संस्थान के अंदर देखे वे एकदम चौकाने वाले थे, करिश्माई थे, जादूई थे। तो वो भी अचानक से संभव नहीं हुआ। पहले की सरकारों की लापरवाही और इस सरकार की जो अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार आई उसकी जनता के प्रति जवाबदेही, जनता के प्रति उनका प्यार, जनता के प्रति उनका समर्पण, त्याग, संघर्ष वो इस बात का नतीजा था कि जो दशकों से चरमराई हुई स्वास्थ्य सेवायें हैं सरकारी विभाग की जो स्वास्थ्य सेवायें हैं वो चंद सालों के अंदर सही दिशा में आगे बढ़ने लगीं और सिर्फ सही दिशा में आगे नहीं बढ़ीं, बल्कि आखरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को समय के अंदर बेहतर से बेहतर और बिल्कुल निशुल्क उसको इलाज मिले, इसके लिए हमारे माननीय मंत्रियों ने हमारे विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिन-रात एक कर कर इसको जमीन पर उतारने का काम किया। तो जो चीज पहले खराब थी, बीच में कुछ चुनिंदा लोग आते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी लोग आते हैं जो आम जन को अपने परिवार के सदस्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं और उसके लिए 24 घंटे सातो दिन तत्परता से लगे होते हैं और उन चीजों का फिर एकाएक उसी ढ़र्रे पर आकर ठप्प हो जाना, उसी ढ़र्रे पर

आकर रुक जाना, उसी तरीके से जैसे पहले मरीजों का अधिकारियों के साथ बदतमीजी भरा रवैया होता था वो दोबारा से होना, तो ये पूरा का पूरा एक राजनैतिक साजिश करने का और राजनैतिक साजिश के तहत दिल्ली की जनता को परेशान करने का घटनाक्रम नजर आता है। सिर्फ दवाइयों की कमी नहीं, सिर्फ इक्युपमेंट्स जो हैं चिकित्सा के उनकी कमी नहीं, स्टाफ की कमी नहीं बल्कि जो डॉक्टर्स पूरा समय के अंदर अपनी नौकरी करते थे पूरी ईमानदारी से करते थे अब वो कुर्सियों से भी नदारद हैं। तो निश्चित तौर पर जो ये नौकरशाह हैं, जो ये कठपुतली बने हुए बैठे हैं चुने हुए लोगों पर सिलेक्टेड लोगों की जो पावर का यूज हो रहा है, ये बेहद दुख का विषय है और बेहद शर्म का विषय भी है कि लोकतंत्र के अंदर आजादी के इतिहास में पहली बार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को किस प्रकार से पंगु बनाने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से उनको शक्तिहीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है ये जनता देख रही है और ये अनायास नहीं हो रहा अध्यक्ष जी कि हम बोल दें की किसी का मन करा की अचानक से जो है अस्पतालों की दवाइयां रोक दे, सैलरी रोक दे, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को हटा दे, ये अचानक नहीं हो रहा। इन्होंने देखा है कि किस प्रकार से एक वो पार्टी जो 49 दिन की अपनी सरकार चलाती है और 49 दिन की सरकार के अंदर ही जनता उनके काम से इतनी खुश होती है, उनकी ईमानदारी और इतनी मेहनत से लोगों को वो अपना बना लेते हैं कि वो महज एक साल के अंदर जब दोबारा चुनाव होता है 2015 के अंदर तो वो 67 सीटें लेकर आते हैं प्रचंड बहुमत

आज तक के इतिहास में पहली बार और ये रिकार्ड शायद खुद हम भी न तोड़ पाएं। तो इसको कैसे बीट किया जाए, इसको कैसे परेशान किया जाए। इनके विधायक भी नहीं टूटते, इनके ऊपर हम रेड मारते हैं तो वहां से भी कुछ नहीं निकलता। झूठे-सच्चे केस लगाकर हम इनको अंदर कर देते हैं, अपराधिक छवि इनकी बनाने का प्रयास करते हैं तो माननीय न्यायालय जो है इनको बाइज्जत बरी कर देते हैं तो अब कैसे इन लोगों से पार पाई जा सके। तो ऐसे में दिल्ली की जनता जो हर बार इनके मुंह पर हार का तमाचा जड़ती है, अब केन्द्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ सीधी दुश्मनाई और सीधा जो है अपना हिसाब-किताब करने का फैसला किया है। क्योंकि दिल्ली में आप देखिये 2 करोड़ लोग रहते हैं, इन 2 करोड़ लोगों में से लगभग 80 फीसदी लोग अध्यक्ष जी ऐसे हैं जो झुग्गी-झोपड़ी में रहते होंगे, जो रि-सेटलमेंट कालोनी में रहते होंगे, जो डीडीए के जो एलआईजी फ्लैट्स के अंदर रहते होंगे, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के होते होंगे, ऐसे 80 फीसदी लोगों के लिए जब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर एक महीने से ज्यादा अगर सरकारी हस्पताल में ऑपरेशन की डेट मिलती है और मुफ्त में प्राइवेट हस्पताल में उनका ऑपरेशन हो तो किसी सपने से कम नहीं है। ऐसे निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर के पास में खांसी-जुकाम, बुखार की दवाई के लिए प्राइवेट डॉक्टर के पास जहां 500 रुपये की पत्ती जो है देनी पड़ती थी, मुफ्त में वो दवाइयां मिल रही हैं तो किसी सपने के साकार होने जैसा, चमत्कार होने जैसा उनके लिए ये पूरा का पूरा घटनाक्रम था और यही कारण है

कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन-तीन बार हमारे तमाम साथी विधायकों ने माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में अपने मंचों पर जाकर एक ही बात करी कि अगर हमने काम किया है तो ही हमें वोट करियेगा अगर हमने काम नहीं करा तो हमें वोट मत करियेगा,

(समय की घंटी)

श्रीमती राखी बिरला: और जनता ने जो पहली बार जीते उससे कई ज्यादा गुणा मतों से सभी लोगों को जिताकर भेजा। लेकिन अब वो दुश्मनाई जनता के माध्यम से इस प्रकार से निकाली जा रही है कि आपकी दवाइयां रोक दी जाएंगी, आपका ईलाज नहीं होगा, सरकारी बाबू जो होंगे वो आपसे बदतमीजी से बात करेंगे, हर वक्त उन्हें इस बात का अहसास दिलाया जाएगा कि तुमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनाकर, बीजेपी को वोट न देकर अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल करी है और तुम्हारा पानी हम गंदा देंगे, तुम्हारे सीवर साफ करने से हम रोकेंगे, तुम्हारे बच्चों की अच्छी शिक्षा को रोकेंगे और तुम्हारे स्वास्थ्य पर जब बात बन आएगी तो तुम्हारे को नकली दवाइयां या तुम्हें दवाइयां उपलब्ध ही नहीं कराई जाएंगी। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूं कि सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं जिस तानाशाह को इस बात का घमंड है, गुरूर है कि मैं दोबारा लौटकर आउंगा, हो सकता है कि तुम लौटकर भी आ जाओ लेकिन ये तुम्हारे गुनाह कभी भी जनता माफ नहीं करेगी और तुम्हारे ये 400 पार 500 पार के जो ये नारे हैं न मुझे तो तुम 40 से पार होते हुए नजर नहीं आ रहे हो। जिस प्रकार से शर्मिंदगी भरी हरकत, जिस प्रकार से बहूदगीपना रवैया तुम लोगों ने

दिल्ली में अपनाया हुआ है दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को किस प्रकार से रोककर चरमरा कर आप लोग अगर अपनी राजनीति को करना चाहते हो तो परमात्मा सब देख रहा है। जिस राम राज्य की तुम लोग बात करते हो वो तुम सिर्फ बात ही करते हो, उस राम राज्य को वास्तव में स्थापित करने की अगर किसी ने पहल करी है और उस पहल को सफलता पूर्वक कोई आगे लेकर गया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एकमात्र सरकार है वो दिल्ली की सरकार है जिसने हर तबके के व्यक्ति का ख्याल रखा है। तो आज ये दवाइयों की सप्लाई न होना, अपने चिकित्सक के जो हमारे तमाम स्टाफ हैं उनकी सैलरी को रोक देना, तमाम फोर्थ क्लास के लोगों की सैलरी को रोक देना, उनके कांट्रेक्ट्स को रिन्यू न करना, बिल्डिंग्स के काम के अंदर इतनी ढ़िलाई करना ये तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा करती है कि ये राजनैतिक द्वेष के कारण दिल्ली की जनता से सिर्फ और सिर्फ बदला लेने का प्रयास है कि उन्होंने क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उन्होंने क्यों नहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और मैं फिर कहना चाहती हूं तुम कितना ही अत्याचार कर लो दिल्ली की जनता समझती है इस बार भी वो तुम्हारे मुंह पर सिर्फ तमाचा मारने वाली है, वोट की आस तुम दिल्ली की जनता से कतई मत करना। अब मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की भी पहल को और उनकी मेहनत को भी सलाम करना चाहती हूं। अधिकारी सुनते नहीं हैं बार-बार आदेश करने के बाद भी उनकी बात को ठंडे बस्ते में डाला जाता है। खुद ग्राउंड पर जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी एक-एक बात का संज्ञान लेते

हैं। पिछले दिनों संजय गांधी हस्पताल में पूरे 4 घंटे लगाकर एक-एक डिपार्टमेंट का दौरा करा, रिपोर्ट मांगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि मंत्री जी की टेबल पर आज तक वो रिपोर्ट भी सब्मिट हुई होगी। बेहद शर्मिंदगी पूर्ण और बेहद शर्मनाक घटना इस वक्त देश की राजधानी में राजनीति से प्रेरित होकर हो रही है। मैं चाहती हूं अध्यक्ष जी कि चीफ सेक्रेटरी इसका संज्ञान लें और एलजी जो बड़ी-बड़ी बातें करता है दिल्ली के प्रति, वो थोड़ी सी शर्म करे और जितनी भी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर विलंब हो रहा है, देरी हो रही है सेवाओं में उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेंद्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो एक मानवीय मुद्दे के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों के हितों के लिए सबसे पहले अपने हास्पिटलों को ठीक किया। लोगों के हित के लिए उन्हीं के गली-मोहल्लों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के रूप में उनको स्वस्थ रहने के लिए वहीं पर दवाइयां उपलब्ध हों, वहीं पर टैस्ट हों ऐसी व्यवस्था की। लेकिन केन्द्र में बैठी सरकार जो आततायी बनी हुई है उसको सुहाया नहीं। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कहता हूं मैं:

"बदली है राजनीति उन्होंने,

बदली है राजनीति उन्होंने,

बदली है किस्मत उस आम आदमी की जिसे सबने नकारा था।''

जो आम आदमी थे पार्टियां कोई भी थी चाहे पहले कोई भी दूसरी पार्टियां रही हैं या भारतीय जनता पार्टी ळे, लोगों को सभी ने नकारा है।

''बदली है राजनीति हमने,
बदली है किस्मत उस आम आदमी की जिसे सबने नकारा था
कर लो सितम तुम कितने भी अभी वक्त तुम्हारा है
कल वक्त आम आदमी का होगा।''

जो ये आम आदमी है न ये सब कुछ पलट देता है। दिल्ली के अंदर एक समय में 70 में से 67 सीटें दी फिर उसके बाद 70 में से 62 दी। एमसीडी के अंदर भी सरकार बनवाई लेकिन तुम्हें सुहाया नहीं। आदमियों की व्यवस्था को खराब करने के लिए लगे हुए हों। आज हास्पिटलों के अंदर जो दुर्दशा इन्होंने कर रखी है ये तो मैं शुक्र मनाता हूं आपका कि आपने इस चुनाव के दौरान भी इस सेशन को बुलाने की हिम्मत दिखाई और लोगों के हितों के लिए आप बार-बार सेशन बुला रहे हैं। इसी डर के मारे इन्होंने अभी एक ऑर्डर पास किया है दवाइयां पूरी नहीं हैं तो आप परच्येज कर सकते हो लेकिन वो परच्येज भी कौन सी होती हैं जब मरीज हास्पिटल के अंदर दाखिल होता है उसको दो दिन, चार दिन, दस दिन वहां पर रहना होता है उसके लिए तो वो परच्येज कर सकते हैं लेकिन ओपीडी के अंदर जिस समय मरीज जाता है तो उसको वो दवाई नहीं मिलती है जिसकी मैं आपको रिटन के अंदर आपकी टेबल के ऊपर भेज रहा हूं 1 से 148 नंबर

तक है और मैंने अपने साइन भी किये हुए हैं। इसके अंदर यदि एक भी दवाई उपलब्ध हो तो मैं इस सदन से इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हूं क्योंकि जो कहता हूं बिलकुल सच कहता हूं। ये लिस्ट जो जरूरी दवाइयों की है ओपीडी के अंदर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति तो हास्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होता, इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती। आज मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर दवाई नहीं मिल रही है। अरे जब पहले हम 95, 98 परसेंट तक दवाइयां उपलब्ध करवाते थे ऐसा आज क्या हो गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक ही बात सोचते थे ये पैसा जनता का पैसा है और जनता के हितों के लिए वो पैसा खर्चते हैं। तो ये पैसा हम लोगों का नहीं है अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है। बस अरविंद केजरीवाल जी तो उसके एक मुखिया बने हुए हैं कि वो जनता का पैसा जनता के हितों के लिए खर्चा जाएगा लेकिन इस पैसे की रोक के लिए केन्द्र सरकार ने एलजी साहब को ऐसा बिठा रखा है कि सारी व्यवस्थाओं को तहस-नहस करने का ठेका ले रखा है। फरिश्ते योजना थी, देश का कहीं का कोई भी व्यक्ति दिल्ली के अंदर आकर कुदरतन कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो तो उस योजना के तहत उसका इलाज फ्री में हो जाता था और मैं सही बात कह रहा हूं आज हालांकि मुझे ऐसे शब्द निकालने नहीं चाहिए। यदि उनका कभी नजदीकी रिश्तेदार का यहां पर दिल्ली की सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो गया और उसको इलाज नहीं मिला तो उस दिन पता लगेगा और जब उसको गाली देगा क्योंकि भगवान की लाठी जब चलती है तो वो दिखती नहीं है, अच्छे-अच्छों के होश ठिकाने लगा देती है। मैं बस यही

कहना चाहूंगा और आपको सेल्यूट करता हूं इस बात के लिए कि आप बार-बार इस सदन को बुला रहे हैं और इस सदन को एक चीज के लिए और बुलाएं और आप हिम्मत दिखाएं इस बात के लिए कि जो इलेक्ट्रोरल बांड का एक खाका आया है आपके सामने मैं कहता हूं दिल्ली विधानसभा की तरफ से भी एक रिट ऐसी दायर हो उसका पूरा का पूरा खुलासा करते हुए दिल्ली सरकार उस केस को लड़े, इस प्रकार की भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि जिस शराब नीति के तहत अरविंद केजरीवाल जी को अंदर किया गया है उनके ऊपर तो मनीट्रेल का अभी तक कुछ मिला ही नहीं। संजय सिंह जी को अंदर किया है मनीट्रेल का उसके अंदर कुछ नहीं मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मनीट्रेल का कहीं पर संजय सिंह के खिलाफ में आज तक साबित नहीं हुआ, 6-6 महीने उनके गुजार दिये, जेल की सलाखों के पीछे रखा है। संजय सिंह को अंदर क्यों किया क्योंकि वो शेर की तरह दहाड़ता था और उस सदन के अंदर देश के उस व्यक्ति के कानों के कीड़े झड़ जाते थे जब संजय सिंह बोलता था। उन्हें सुहाया नहीं क्योंकि वो लोगों के हितों की आवाज उठाते थे, दिल्ली की आवाज को उठाते थे। इसी प्रकार से दिल्ली के हितों के लिए, देश के हितों के लिए पंजाब के अंदर भी अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर भी काम कर रहे थे और उनको लगा कि अरविंद केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री हो सकता है तो इसी नाते उन्होंने उसको अंदर किया है। लेकिन यहीं पर रुकने वाला नहीं है मामला। कभी ये दिल्ली इंद्रप्रस्थ भी हुआ करती थी, कौरव हुआ करते थे,

कौरव भी एक समय के अंदर इसी प्रकार से थे जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी है। पूरे के पूरे राज्यों के अंदर उस समय भी कौरवों का आधिपत्य होता था आज भी बीजेपी का आधिपत्य है। जिस प्रकार से कौरव मिट गये मिटने में देरी इनके भी नहीं लगेगी। इसी के अंदर मैं कहता हूं:

"महाभारत में चली ऐसी कालचक्र ने चाल
युद्ध भयंकर हुआ और कौरव हुए बेहाल।
महाभारत में चली कालचक्र ने ऐसी चाल
युद्ध भयंकर हुआ और कौरव हुए बेहाल
आज समर भूमि में भी वो दिन फिर दोहराया है
मोदी तुम्हारे चरित्र में दुर्योधन नजर आया है,
मोदी तुम्हारे चरित्र में दुर्योधन नजर आया है।"

मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं मोदी जी इतने आतातायी मत बनो। जिस प्रकार से दुर्योधन ने और दुश्शासन ने महाभारत के अंदर घटिया चालें चली थीं लेकिन जीत किसकी हुई, जीत हुई पांडवों की क्योंकि वो सत्य के साथ थे। अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ में है। लोगों को पीने के लिए फ्री में पानी देता है, बिजली फ्री में देता है, माताओ के लिए बहनों के लिए बेटियों के लिए दिल्ली की बसों को फ्री में कर रखा है। लोगों के स्वस्थ रहने के लिए अरविंद केजरीवाल ने..

(समय की घंटी

श्री महेंद्र गोयलः सभी के सभी हास्पिटलों के अंदर दवाइयों को भी फ्री किया है और महंगे से महंगे टैस्ट को भी फ्री किया है। ये मानवीय सेवाओं के ऊपर आप इस प्रकार का रोकने का प्रयत्न मत करो। आप में हिम्मत है तो पूरे देश के अंदर बहुत से राज्यों के अंदर आपकी सरकारें हैं वहां के हास्पिटलों को भी आप ठीक करो। फरिश्ते योजना लाकर वहां पर भी आप रोड एक्सीडेंट के अंदर कहीं पर किसी आदमी को जरूरत पड़े तो उनका भी इलाज कराओ। आप गली के अंदर मोहल्ले के अंदर आप भी क्लिनिक खोलो नाम चाहे आप कुछ भी रखो। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी केन्द्र रख दो आप। अरे खोल तो लो, अडानी केन्द्र रख लो, अंबानी केन्द्र रख लो या कोई और केन्द्र रख लो लेकिन ये जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर ये काम हुए हैं और ये पहली सरकार है जो हिम्मत दिखाती है। यदि सरकार के किसी भी चीज के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई कमी होती है तो वो खुद आवाज उठाने की हिम्मत रखती है ये इस प्रकार से आपने जो आज इस सदन को बुलाया है, आपको मैं सेल्यूट करता हूं। बार-बार इसी प्रकार से आप इस सदन को बुलाते रहे हैं ताकी उनको पता लगे। जिस प्रकार से अभी इन्होंने ऑर्डर रिलीज किया है दवाइयों की कुछ पूर्ति करवाई क्योंकि बहुत समय से चल रहा था कि हम स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए सेशन बुलाएंगे। आज की तारीख निश्चित की तो आज कैसे इतनी दवाइयां पूरी हो गईं हैं, कहीं न कहीं वो रोकी गई थी। यदि आप सेशन नहीं बुलाते तो ये ऐसे ही चलता रहता।

तो बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और इसी के अंदर कुछ लाइन कहता हूं:

"तब था इंद्रप्रस्थ,

तब था इंद्रप्रस्थ आज दिल्ली है,

तब थे कौरव आज भाजपाई हैं,

तब था शतरंज आज तानाशाही है,

तब थी कौरवी सेना, आज ईडी और सीबीआई है,

आज ईडी और सीबीआई है।"

और अरविंद केजरीवाल जी सलाखों से बाहर आएंगे मुझे इस बात का पूरा यकीन है। जिस प्रकार से संजय सिंह आए हैं मनीष सिसोदिया जी भी आएंगे सत्येन्द्र जैन साहब भी आएंगे और जुल्म वो कितना भी कर लें। हमारे विधायकों के ऊपर भी बहुत से केस कभी भी बनवाने में वो पीछे नहीं हटते लेकिन दिल्ली का एक भी विधायक आज तक नहीं टूटा है। तो मैं सभी विधायकों को सेल्यूट करता हूं कि इसी प्रकार से एकजुट होकर जनता के हितों के कार्यों को आप भी करते रहें, हम भी करते रहें और दिल्ली की जनता के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर इसी प्रकार से हम ये काम करते रहें जय हिन्द-जय भारत।

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई मुझे राखी जी की जगह आपका नाम दिया गया था, राखी जी आ गई इसलिए ड्रॉप हो गया प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी चर्चा..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई अजय दत्त जी अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री खड़े हैं, बैठिये प्लीज।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि एक बहुत गंभीर मामले पर आपने ये सदन बुलाया। राजेन्द्र पाल गौतम जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मामला कालिंग अटेंशन रूल-54 के अंदर उठाया और राजेन्द्र पाल गौतम जी के विषय में मैं कह सकता हूं कि जब भी इनके एरिया में मैं गया हूं ये उस हस्पताल के अंदर आए हैं और इनको उन हस्पतालों के बारे में अच्छी-खासी जानकारी रही है। कई बार पत्रों के माध्यम से भी इन्होंने सरकार को उन हस्पतालों की कमियों के बारे में अवगत कराया है। बहुत सारे विधायक साथी यहां पर बोले संजीव झा जी बोले, महेन्द्र गोयल जी बोले, राखी बिडलान बोलीं, सब लोगों का बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, ये मामला करीब दो महीने से भी ज्यादा पुराना मामला है। करीब जनवरी के अंदर इस तरीके का फीडबैक आने लगा था कि हस्पतालों में दवाइयों की कमियां हो रही हैं।

ये भी फीडबैक आ रहा था कि मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर टैस्ट जो थे वो बंद कर दिये गये हैं और इस विषय के अंदर मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी चिंता जताई थी, कई बार मुझे कहा और मैंने इस विषय में खुद पता किया, स्वास्थ्य सचिव से बात हुई, डिपार्टमेंट में कई बार बात हुई, कई बार डायरेक्शंस मौखिक दी गयी और अंततः जब इसके उपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी तो जो हैड ऑफ ब्यूरोक्रेसी होते हैं नरेश कुमार जी मुख्य सचिव हैं, उनको मैंने 12 फरवरी 2024 को रिटन डायरेक्शन दी कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयों की कमी हो रही है लिहाजा इसपे कार्रवाई करें।क्या दवाइयों की कमी है हां या? अगर है तो इसके लिये आपका क्या प्लान है, टाईमलाईन के साथ मुझे सब्मिट करिये। क्या टैस्ट्स बंद हो गये हैं मोहल्ला क्लिनिक्स में जो टैस्ट हुआ करते थे? यदि हां, तो इसका प्लान सबमिट कीजिये कि कैसे शुरू होंगे। ये मैंने उनको कहा, उनकी तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया हुई नहीं, कोई जवाब उनसे मेरे पास आया नहीं। मैंने दोबारा उनको 4 मार्च को फिर लिखा यही बातें कि क्या दवाइयों की कमी है, हां या न, क्या टैस्ट बंद हो गये हैं हां या न, हो गये हैं तो इसका प्लान दीजिये। उनकी तरफ से कोई प्लान मेरे पास नहीं आया। उसके बाद मैंने 18 मार्च को दोबारा उनको रिटन डायरेक्शन दी कि आप इसके उपर कार्रवाई कीजिये। और मुझे लग रहा

है उसी के आसपास राजेन्द्र गौतम जी ने भी यहां पे रूल 54 लगाया और उसके बाद मैंने दोबारा उनको फिर 19 मार्च को लिखा कि भई ये रूल 54 के अंदर डिस्कशन है आप सुबह सुबह विधान सभा आईयेगा, मुझे ब्रीफ कीजियेगा और यहां पे उपलब्ध रहियेगा आप। उन्हें उपलब्ध होना चाहिये था, वो आज उपलब्ध नहीं हैं, ये भी दुख की बात है। उन्हें होना चाहिये था, मैंने उनको रिटन डायरेक्शंस दी थी कि उनको उपलब्ध होना है। बहरहाल अध्यक्ष जी, समस्या ये है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एक तय षडयंत्र के तहत दवाइयों की कमी की जा रही है और ये मैं आन रिकार्ड बोल रहा हूं यहां पे इस विधान सभा के अंदर। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में, डिस्पेंसरियों में दवाई लाने का एक तय तरीका है, एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी नाम की एक सीपीए है जिसका काम है कि वो टेंडर करती है दवाइयों की और वो दवाइयां अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर उपलब्ध कराई जाती हैं। ये टेंडर हर साल किया जाता है। आपको और सदन को हैरानी होगी और जो पत्रकार इसको सुन रहे होंगे उनको हैरानी होगी सीपीए का टेंडर जो 2023 में किया गया वो लगभग एक साल तक उस टेंडर को फाइनलाईज नहीं किया गया, उसके अंदर बिड आ गयी थी, एक साल तक उस टेंडर को फाइनलाईज नहीं किया गया और फिर एक साल जब बीत गया जाहिर सी बात है जब एक साल का टेंडर है एक कंपनी ने एक साल के लिये अपने रेट दिया है कि इस एक साल में हम ये अमुक दवाई इस रेट पे देंगे, जब वो एक साल पूरा हो गया तो वो रेट अब बढ़ायेगी, या घटायेगी तो वो टेंडर

खत्म हो गया और अब दोबारा अब मार्च में दोबारा टेंडर किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक तय षडयंत्र के तहत किया गया कि जब सीपीए का टेंडर ही नहीं होगा तो दवाइयां उपलब्ध नहीं होंगी, जब दवाइयां उपलब्ध ही नहीं होंगी तो क्या अरविंद केजरीवाल कर लेंगे, क्या सौरभ भारद्वाज करेंगे, नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं। मैंने बार बार लिखा है कि ये टेंडर किसकी गलती की वजह से, किन अधिकारियों की गलती की वजह से नहीं हुआ उन दोषियों का नाम बताया जाये, उसके उपर मुझे अभी तक कोई नाम नहीं दिये गये कि ये लोग हैं जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये टेंडर नहीं दिया या इन्होंने टेंडर नहीं होने दिया। अब अगर सीपीए के जरिये दवाइयां नहीं आती हैं तो उसके और कुछ आल्टरनेटिव तरीके हैं कि इन जरियों से आप दवाई ले सकते हैं उसको मोटे तौर पे कह सकते हैं लोकल परचेज या अस्पताल लोकली अपने रेट कांट्रेक्ट से दवाई ले ले। मैंने जितने भी अस्पताल हैं सभी के जो एमएस और एमडी हैं उनकी मीटिंग बुलायी 1 मार्च 2024 को और उसके बाद दोबारा उन सबकी मीटिंग बुलाई 11 मार्च 2024 को जिसके अंदर उन्होंने मुझे बताया कि जो लोकल परचेज और जो रेट कांट्रेक्ट से भी दवाइयां ली जाती हैं उसके विषय में भी हैल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे सर्कुलर निकाल दिये हैं जिससे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो दवाइयां आयें, यानि कि कुल मिला के पूरा का पूरा षडयंत्र इस तरीके से किया गया एक योजना बनाई गयी कि दिल्ली के अंदर अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध न हों। अब अध्यक्ष जी, हम सब तो यहां पे समृद्ध लोग हैं सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं भी मिलेगी तो आप

कहीं न कहीं से ले लोगे खरीद लोगे। और मैं मानता हूं चाहे वो हैल्थ सेक्रेटरी हों, चाहे वो मुख्य सचिव हों, चाहे वो एलजी हों इनमें से कोई भी आदमी सरकारी अस्पताल की दवाइयों पे आश्रित नहीं है। ये लोग समृद्ध लोग हैं। मगर अध्यक्ष जी, ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी बीमारियों के लिये और दवाइयों के लिये सिर्फ और सिर्फ मोहल्ला क्लिनिकों पे, डिस्पेंसरियों में और इन अस्पतालों पे आश्रित हैं। उनके पास और कोई सहारा नहीं है उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो बाजार से दवाइयां खरीद लें और ये बात मैं सिर्फ खांसी जुकाम की नहीं कर रहा अध्यक्ष जी, किसी को किडनी की बड़ी गंभीर बीमारी है जब तक दवा चलेगी तब तक सांस चलेगी, दवा बंद, कुछ दिनों में गुजर जायेगा आदमी। अपना पूरा पूरा परिवार चलाने वाले लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, लीवर का कोई गंभीर समस्या है, किडनी की गंभीर समस्या है, न्यूरो डिसऑर्डर है और उनका पूरा का पूरा परिवार इस चीज पे आश्रित है कि उनको सरकारी अस्पतालों से, मोहल्ला क्लिनिकों से दवाइयां मिलती हैं। अगर ऐसी जगह आप दवाइयां बंद कर देंगे तो अध्यक्ष जी आप सोचिये जो लोग बीमार हैं वो गंभीर बीमार होंगे, जो लोग गंभीर बीमार हैं हो सकता है भगवान न करे उनकी मृत्यु भी होगी। उनका दोषी कौन होगा, कोई तो दोषी होगा। आप कहते हैं कि कोई भी चीज गलत हो जाये तो उसके लिये कोई न कोई दोषी होगा, हमारे वकील साहब बैठे हैं मदन लाल जी है, राजेंद्र गौतम जी हैं, मैं अपने वकील साथियों से जानना चाहूंगा कहा जाता है 'wherever there is an illegality, there is a remedy' कानून में

उपलब्ध है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या दवाइयां उपलब्ध न होने की वजह से कोई आदमी गंभीर बीमार पड़ेगा, कोई आदमी मरेगा, क्या इसके लिये कानूनी प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिये किसी का, किसी के उपर तो मुकदमा होना चाहिये? हो सकता है पुलिस दर्ज न करे, हम कंप्लेंट देंगे, पुलिस दर्ज नहीं करेगी हम 156(3) में जायेंगे। हम मुकदमा दर्ज करायेंगे, इस बार हम ऐसे खाली नहीं बैठने वाले है। मुख्य सचिव और हैल्थ सचिव के नाम पे मुकदमा दर्ज करवाउंगा मैं इस चीज के लिये। अगर किसी के लिये भी जो है ऐसे नहीं जाने देंगे, बहुत कर लिया हमने, हमने बहुत कर ली लिखत पढ़त। बार बार एलजी साहब को लिखा जा रहा है कि आपके मुख्य सचिव और आपके स्वास्थ्य सचिव जानबूझ के दवाइयों की कमी को छिपा रहे हैं। अब अध्यक्ष जी आगे का मामला क्या है? पहली बात तो ये है कि दवाइयों की कमी है, मैंने 27 मार्च को यहीं पे विधान सभा में हमारा हाउस था उसके लिये बुलाया, जिस दिन हाउस था 27 होगा या 28 होगा, सुबह सुबह मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव मेरे कमरे में 10 बजे मौजूद थे, उन्होंने मुझे कहा ऑन रिकार्ड कहा कि किसी भी सरकारी अस्पताल में, मोहल्ला क्लिनिक में कोई दवाइयों की कमी नहीं है, दवाइयां उपलब्ध हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ अध्यक्ष जी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है वरना मैं खुद ही जाके जो है इंस्पेक्शन कर लेता, पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से मैं जो है अफसरों के साथ अस्पतालों के निरीक्षण में नहीं जा सकता था। मैंने एलजी साहब को पत्र लिखा इस बारे में कि मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव मुझे मिसलीड कर रहे

हैं, मुझे गुमराह कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है। लिहाजा सरकार को गुमराह करने के लिये इनके उपर कार्रवाई की जाये। उपराज्यपाल ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे ये समझ में आता है कि जो मुख्य सचिव कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य सचिव कर रहे हैं खुद नहीं कर रहे, उपराज्यपाल शामिल हैं इसके अंदर। अगर उपराज्यपाल शामिल नहीं होते तो अब तक उपराज्यपाल इसपे कार्रवाई करते। उपराज्यपाल उलटा मेरे को जो है एक राजनीतिक चिट्ठी लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई आपको सीधी सीधी बात पूछी है कि मुख्य सचिव इज मिसलीडिंग। he is misleading the govt. about availability of medicines. अब मैं इन्हीं पे आ रहा हूं। अब अध्यक्ष जी आज हाउस है संजीव झा जी ने खुद अपने बुराड़ी अस्पताल की पर्चियां पड़ी हैं इस हाउस में। हमने पूछा आज की है, कल की हैं, आज की पर्चियां हैं। मरीजों का नाम भी बताया, डॉक्टर का कमरा नंबर भी बताया, दवाइयां नहीं हैं। महेंद्र गोयल जी ने तो इतनी लंबी लिस्ट दे दी बीएसए हॉस्पिटल की। इतनी लंबी लिस्ट दे दी 148 दवाइयों की और वो कह रहे हैं कि ये अवेलेबल हों तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब अध्यक्ष जी मैंने अस्पतालों में सुबह सुबह जब मुख्य सचिव मेरे यहां आये साढे दस बजे तक यहां थे मेरे कमरे में, 11 बजे से हाउस था तो मैंने एक दो लोगों को कहा मेरे घर के पास मालवीय नगर हॉस्पिटल है कि भई जाके देख के आओ, जो मरीज हैं उनके पर्चे ले लो। अध्यक्ष जी बदमाशी इस हद तक है कि डॉक्टरों को ये कहा गया है जो दवा उपलब्ध न हो वो लिखो ही मत। आप

सोचिये, वो दवा जो दवा उपलब्ध न हो उसके बारे में जिक्र ही मत करो ताकि ये चीज पर्चे पे न आ जाये कि दवाई उपलब्ध नहीं है, क्यों? क्योंकि 27 तारीख को मुख्य सचिव ने मुझे ये लिखित में दे दिया कि सारी दवाइयां उपलब्ध हैं। और मैंने इसके लिये उपराज्यपाल को खत लिख दिया कि क्योंकि मुझे झूठ बोला गया, सरकार को झूठ बोला गया इनके उपर कार्रवाई किया जाये। तो एक झूठ को छुपाने के लिये सौ झूठ बोले जायेंगे अब। तो अध्यक्ष जी ये मालवीय नगर का पर्चा आप देख सकते हैं ये मैंने हरा लगाया है ये उपलब्ध नहीं है। मरीज का फोटो भी लिया है इसमें ये देखिये ये, ये उपलब्ध नहीं है। मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल ये उपलब्ध नहीं है। मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल ये उपलब्ध नहीं है। पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल दो दवाइयां उपलब्ध नहीं है, तीन में से एक दवाई उपलब्ध नहीं है। तीन में से एक दवाई उपलब्ध नहीं है। लोक नायक हॉस्पिटल, डॉक्टर आशीष गोयल, लोक नायक हॉस्पिटल एक दो तीन चार पांच, पांच में से दो दवाई उपलब्ध नहीं है। आज की है अध्यक्ष जी ये? लोक नायक हॉस्पिटल तीन में से दो उपलब्ध हैं एक उपलब्ध नहीं है। जीबी पंत हॉस्पिटल सात में से तीन उपलब्ध नहीं है। और ये खूब हैं। अध्यक्ष जी मैंने आज मुख्य सचिव से पूछा कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर खबर छपी है आज ये, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये खबर छपी है और छोटी मोटी खबर नहीं है। पांच कालम की खबर है जिसके अंदर कई अस्पतालों का हमारा जिक्र है कि वो कह रहे हैं कि इन अस्पतालों के अंदर consumables और दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। मुख्य सचिव कहते हैं

स्वास्थ्य सचिव को कि इस अखबार को नोटिस दे दो। कमाल है। मुख्य सचिव का जवाब ये है इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि आपके तीन अस्पतालों में उन्होंने दौरा किया वहां दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। मुख्य सचिव का जवाब ये है स्वास्थ्य सचिव को कि इस अखबार को नोटिस दे दो। कमाल हो गया, shoot the messenger, हैं न? इसको भी नोटिस दे दो, संजीव झा को भी नोटिस दे दो, महेंद्र गोयल को भी नोटिस दे दो, एक मुझे भी दे दो। और एक राखी बिरला को दे दो। अध्यक्ष जी कहां जा रहा है ये देश? मतलब क्या बना के छोड़ेंगे हम इस चीज को? मेरे पास जब वो 27 तारीख को आये मैंने मुख्य सचिव को कहा देखिये ये लड़ाई झगड़े का काम नहीं है, दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं ये एक सीरियस मामला है लोग मर जायेंगे। आप सोचो उनके बारे में। कोई फर्क ही नहीं है। कोई फर्क नहीं है। अब क्या किया जा रहा है जो महेंद्र गोयल जी बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोकल परचेज कर ली मगर लोकल परचेज सिर्फ जो मरीज उस अस्पताल में एडमिट है उसके लिये किया जा रहा है। जो ओपीडी का पेशंट है उसके लिये लोकल परचेज नहीं होता है। करते ही नहीं है अस्पताल क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ती है वो दवाई। सीपीए की दवाई सस्ती पड़ती है, लोकल परचेज की महंगी पड़ती है। मगर सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। फिर मैंने आज जो रिपोर्ट लाये थे मैंने उसमें बोला कि मोहल्ला क्लिनिकों की तुम्हारी रिपोर्ट में ही लिखा है कि 50 परसेंट दवाइयां अवेलेबल नहीं हैं, 40 परसेंट दवाइयां अवेलेबल नहीं हैं। तो कह रहे हैं नहीं साहब इनका सब्सटिट्यूट हो जायेगा। कमाल है। ये कैसे संभव है

अगर सब्सटिट्यूट हो जायेगा तो इनको क्यूं नहीं दी गयी दवाइयां? और अध्यक्ष जी ये जो दवाइयां कुछ दिनों में उपलब्ध भी हुई हैं 15 दिनों में ये भी इस दिल्ली विधान सभा की वजह से हैं जिसकी वजह से ये दवाइयां उपलब्ध हो गयी अध्यक्ष जी। अगर आप ये सेशन न बुलाते और राजेंद्र गौतम जी ये नियम 54 के अंदर इस असेम्बली के अंदर ये डिस्कशन न बुलाते तो आज मर रहे होते लोग दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर हाहाकार मच गया होता, दिल्ली के अंदर त्राहि त्राहि हो जाती जिस तरीके से ये षडयंत्र किया गया था। और बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हाउस को गुमराह करने के लिये ये रिपोर्ट दी गयी है तो मैंने दोनों रिपोर्ट अध्यक्ष जी आपके सामने रख दी। अफसरों की रिपोर्ट मुख्य सचिव की और स्वास्थ्य सचिव की रिपोर्ट ये है कि सभी दवाइयां, सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में उपलब्ध हैं। जो उपलब्ध नहीं हैं उनकी जगह जो है आल्टरनेटिव उपलब्ध है यानि कि दवा सबको मिलेगी। और जो मेरे विधायकों की रिपोर्ट है, अखबार की रिपोर्ट है, मैंने जो पता किया वो रिपोर्ट है वो ये है कि अभी भी दवाइयों की कमी है। अब मुझे नहीं मालूम कि मंत्री के तौर पे मुझे कौन सी रिपोर्ट रखनी चाहिये, मैंने दोनों रिपोर्ट आपके सामने रख दी और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने उठाया। एक और अध्यक्ष जी मैं बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कुछ दिनों पहले चूंकि अध्यक्ष जी इस विधान सभा को मालूम होना चाहिये कुछ दिनों पहले 31 जनवरी 2024 को बीएसए हॉस्पिटल बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के साथ एक हमारा मेडिकल कालेज अटैच्ड है उस मेडिकल कालेज की दो

छात्राओं का वाय वा था प्रैक्टिकल टैस्ट जो होता है वो था। उस टैस्ट के अंदर एक प्रोफेसर ने जिन्होंने उनका वाय वा लिया उन्होंने उनके साथ कई सारी ऐसी बातें कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिये थी। उनको महिलाओं के गुप्तांग के विषय में खास तौर पे बातें पूछी गयी। मैंने पूछा उन के दूसरे जो थे वहां पे वार्डन थे क्या जिस सब्जेक्ट का वाय वा हो रहा था उसमें महिलाओं के गुप्तांग के विषय में सब्जेक्ट है? उन्होंने बोला उसका लेना देना नहीं, वो तो फार्मेसी से रिलेटिड सब्जेक्ट है। उसके अंदर उस चीज का कोई लेनादेना नहीं। उन बच्चियों से ऐसे ऐसे शब्द पूछे गये, उनको छूने की कोशिश की गयी, उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया और ये साधारण बच्चियां नहीं हैं अध्यक्ष जी, एमबीबीएस की बच्चियां हैं। आप सोच सकते हैं अगर बीएसए कालेज के अंदर एमबीबीएस में आ रही हैं तो वो इंडिया की टॉपर लड़कियां हैं, सबसे अव्वल लड़कियां हैं वो। एक लड़की हरियाणा की थी, एक लड़की यूपी की थी। उन बच्चियों ने 31 जनवरी को ही कंप्लेंट की इस विषय में कि हमारे साथ ये किया गया। खैर उनको कहा गया कि इसके उपर कार्रवाई होगी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बना दी गयी। उस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने कुछ किया नहीं, उनके उपर दबाव बनाया गया अस्पताल की तरफ से, मेडिकल कालेज की तरफ से कि आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। उन लड़कियों को एक झूठे आरोप के अंदर ?ंसाने की कोशिश की गयी, उनके मां बाप को बुला के धमकाया गया कि आपका कैरियर खराब कर देंगे, आपके बच्चों का, कंप्लेंट आप वापिस लीजिये। वो बच्चियों ने अपनी कंप्लेंट वापिस नहीं ली अध्यक्ष

जी और उसके बीस इक्कीस दिन बाद उन्होंने पुलिस के अंदर भी अपनी एफआईआर दर्ज करा दी, कालेज ने नहीं दर्ज कराई, उन बच्चियों ने, दोनों बच्चियों ने इंडिविजुअली अलग अलग जाके अपनी एफआईआर दर्ज कराई क्योंकि उनको लगा कि कालेज से, प्रशासन से उनको न्याय नहीं मिल रहा इसलिये उन्होंने एफआईआर दर्ज करायी। ये मामला पूरा फरवरी बीत गया, आधा मार्च बीत गया, मुझे याद है 18 मार्च को ये मामला सोशल मीडिया के संज्ञान से मेरे संज्ञान में मेरे सेक्रेटरी लाये कि ऐसा ऐसा कुछ बीएसए मेडिकल कालेज में हुआ है। मैंने पता किया, फोन कराया मेडिकल कालेज के अंदर कि इन बच्चियों को बोलो कि मैं मिलना चाहता हूं। कालेज की तरफ से कहा गया कि नहीं नहीं इनके एग्जाम हैं ये नहीं मिल सकती। मैंने दबाव डाला, मैंने कहा कोई बात नहीं कार का इंतजाम करो, वो आयें अपने वार्डन के साथ मैं एक बार मिलना चाहता हूं, मैं चाहता था अध्यक्ष जी एक बार देखा जाये कि मामला क्या है। वो बच्चियां अपनी दो सीनियर्स के साथ और अपनी वार्डन के साथ मेरे यहां आई, उन्होंने अपनी सारी आपबीती बताई और अध्यक्ष जी सच और झूठ में फर्क अलग नजर आता है। ऐसा नहीं है कि जो झूठ बोल रहा है जो सच बोल रहा है उसके अंदर समझ में ही नहीं आ रहा आपको कि क्या सच है क्या झूठ है। और दो बच्चियां एक ही प्रोफेसर के बारे में बोल रही हैं और दोनों बच्चियां टॉपर लड़कियां हैं, वो क्यों बोलेंगी किसी के विषय में। मैंने प्रिंसिपल से बात की फोन पे। प्रिंसिपल प्रोफेसर की तरुदारी ले रहे हैं और कह रहे हैं सर आप नहीं जानते ये लड़कियां जो हैं बहुत तेज हैं,

इन लड़कियों ने फोर्जरी की है, मैंने इन लड़कियों के उपर जो है इंक्वायरी बिठा रखी है। ये तो कमाल ही हो गया! सोचिये आपने और किस चीज की इंक्वायरी, मैंने कहा क्या फोर्जरी हुई है। वो मेडिकल कालेज की लड़कियां सर पढ़ती हैं पूरे दिन, पूरे दिन पूरे रात पढ़ती हैं तो एडमिट कार्ड लेने के लिये लाईन में लगना पड़ता है। तो बच्ची अपनी जगह दूसरी जूनियर को भेज देते हैं कि भई तू चली जा मेरा एडमिट कार्ड ले आ, तो एक बच्ची को उसने भेज के अपना एडमिट कार्ड मंगा लिया उसके लिये फोर्जरी की इंक्वायरी कर दी उन बच्चियों के उपर ताकि वो जो है वो मुकदमा वापिस ले ले और मैंने जब लिखित में पूछा 18 मार्च को ही मैंने स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव को लिखा। मैंने पूछा कि भई डेढ महीना हो गया आपने ये मामला मुझे क्यूं नहीं बताया, तो सुनिये अध्यक्ष जी क्या जवाब आता है। वो कहते हैं कि लड़कियों का जो मोलेस्टेशन है ये सर्विसिज़ का मामला है इसलिये एलजी के आधीन आता है। मतलब मोलेस्टेशन भी अब सर्विसिज़ का मामला हो गया। मोलेस्टेशन सर्विसिज़ का मामला है इसलिये सीधा एलजी के पास आता है, इसलिये मंत्री को हम नहीं बतायेंगे। और मुख्य सचिव भी कह रहे हैं कि हां मंत्री को नहीं बताया जायेगा क्योंकि ये सर्विसिज़ का मामला है। तो डेढ महीने से एलजी क्या कर रहे थे मैं एलजी से जानना चाहता हूं? आपका मामला है न, आपका मुख्य सचिव, आपका स्वास्थ्य सचिव कह रहा है ये मामला सीधा आपके आधीन आता है तो बताईये आपने डेढ महीने तक क्या किया इसमें? कुछ नहीं किया अध्यक्ष जी, कुछ नहीं किया, बैठे रहे इसके उपर। जब

मैंने चिट्ठी लिखी मुख्य सचिव को तो मुख्य सचिव उलटा तरफदारी कर रहे हैं, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की। मैंने मुख्य सचिव से पूछा 40 दिन होने को आये, 40 भी नहीं पचास दिन हो गये थे 18 तारीख तक। करीब 50 दिन होने को आये आपकी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने अब तक रिपोर्ट ही नहीं दी, पुलिस ने चार्जशीट कर दी, आपकी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। तो मुख्य सचिव मुझे ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास 90 दिन का टाईम होता है। तो मतलब वो 90 दिन लेंगे इस छोटे से काम के लिये। और बार बार चिट्ठी करने के बाद खूब एलजी साहब ने बहानेबाज़ी बनाई। एलजी साहब ने बोला कि एनसीसीएसए की वजह से नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री नहीं हैं इसलिये नहीं हो रहा। कोई सस्पेंशन की रिकमंडेशन एनसीसीएसए के पास नहीं थी इसकी। झूठ बोल रहे थे एलजी। जो आरोपी प्रोफेसर सलीम शेख हैं उनके विषय में कोई सस्पेंशन की रिकमंडेशन, मैं ऑन रिकार्ड कह रहा हूं, 18 मार्च जब तक मैंने पत्र लिखा। कोई उनकी सस्पैंशन की रिकमंडेशन नहीं थी, झूठ बोला एलजी ने अपने पत्र मेंकि मुख्यमंत्री नहीं है इसकी वजह से नहीं हुआ। और कल या परसों जाके एलजी ने सस्पैंड किया है उनको। अब कैसे कर दिया? अभी तक तो मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे थे, अब आपने कर दिया। अब देखिये मैं उनके बारे में नहीं जानता कि वो व्यक्तिगत क्या करते हैं। मगर मुझे याद है, महिलाओं के विषय में, डंडा लेकर एक महिला को मारने के लिए उनका फोटो खूब वायरल हुआ है, विडियो है, डंडा लेके गुजरात में। ये चरित्र है और ज्ञान हमें

दे रहे हैं। परसों जाके उस आरोपी प्रोफेसर का सस्पेंशन किया है इन्होंने, परसों जाकर। एक पुरानी लिस्ट है ट्रांस्फर/पोस्टिंग की उसको लेकर घूम रहे हैं, कह रहे हैं नहीं ये तो हमें सबके ट्रांस्फर/पोस्टिंग करने थे उसमें वहां का प्रिंसिपल का भी ट्रांस्फर हो जाता। अरे वो एक अलग बात है ये एक अलग बात है। तुमने कब भेजी, अभी भी चैलेंज कर रहा हूं मैं विधान सभा में एलजी साहब को। एलजी साहब दिखा दें 18 मार्च से पहले उन्होंने कब इस आरोपी प्रोफेसर की सस्पेंशन की सिफारिश भेजी या उन लोगों की सिफारिश ये कहकर भेजी कि ये मोलेस्टेशन केस के अंदर इन्वोल्ड हैं इसलिए इनका ट्रांस्फर किया जाए, कब भेजी दिखाएं एलजी? एक रूटिन के ट्रांस्फर/पोस्टिंग के मामले को लगाकर वापस भेज रहे हैं, नहीं ये तो ऐसे था, ऐसे था। तो बहुत शर्म की बात है, ये तो बहुत छोटी और घटिया बात है। इतने बड़े पद पर बैठकर एलजी साहब इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, बहुत शर्म की बात है और जैसा संजीव जी ने भी कहा, महेंद्र गोयल जी ने भी कहा, कि आपकी लड़ाई हमसे है, आप गरीब जनता को क्यों मारना चाहते हो इसके अंदर। तो मैं अपनी बात को विराम दूंगा अध्यक्ष जी और दुबारा धन्यवाद दूंगा कि कई समस्याओं के बाद भी, कई बहाने बाजियों के बाद भी आपने ये सैशन रखा और इसके अंदर जो है बहुत अच्छी चर्चा हुई और सब विधायक साथियों का धन्यवाद कि उन्होंने चर्चा के अंदर भाग लिया।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद माननीय मंत्री जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः माननीय अध्यक्ष जी मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी के आदेश पर भी जो है अगर चर्चा के दौरान भी सदन की अवमानना करते हुए अगर स्वास्थ्य सचिव यहां नहीं आए हुए हैं या मुख्य सचिव नहीं है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): स्वास्थ्य सचिव आए हैं, मुख्य सचिव नहीं आए हैं।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः मुख्य सचिव नहीं है तो ये बड़ा गम्भीर मुद्दा है, उसको ब्रिच ऑफ प्रिविलेज मानना चाहिए सदन का और उसपर कार्रवाई होनी चाहिए सदन की तरफ से, ये प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सर। ये बहुत गम्भीर मुद्दा है, चीफ सेक्रेटरी को बताए जाने के बावजूद, मुख्य सचिव के द्वारा आदेश देने के बावजूद भी अगर वो नहीं ऐसे गम्भीर मुद्दे पर जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, दिल्ली में लोगों के जानमाल का विषय है, दवाईयाँ नहीं हैं, अगर कोई विषय है तो उसपर जरूर आपको विचार करें और तुरंत ये मामला ब्रिच ऑफ प्रिविलेज का मामला बनाकर करके ये कमेटी को सौंपना चाहिए, ये हमारा निवेदन है आपसे।

श्री महेंद्र गोयलः अध्यक्ष जी, एक ये जो money trail पर आज कल चल रहा है, एक दिन का सैशन बुला लो उसपर चर्चा हो जाए कम से कम। उसपर बहुत जरूरी है क्योंकि एक दिल्ली के मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के आधार के ऊपर उन्होंने अंदर करा हुआ है और जिसके सबूत मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबूत मिल रहे

हैं, जिस शराब कारोबारी के तहत उन्होंने 55 करोड़, साढ़े चार करोड़ रुपए, मतलब उनके कैश हुए, हुए हैं तो इस पर एक बार चर्चा विषय तो बना लो, ये बहुत जरूरी है।

(अपराह्न 1.34 पर
माननीया उपाध्यक्ष श्रीमती राखी बिरला, पीठासीन हुई)

श्री महेंद्र गायेलः माननीया अध्यक्षा जी, जिस समय आप आ रहे थे तो मैंने एक प्रस्ताव रखा था।

माननीया अध्यक्षः मैंने सुना आपका प्रस्ताव और इस पर भी इस चर्चा के बाद विचार करके रूलिंग देते हैं।

श्री महेंद्र गोयलः इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, देश की आंखे खुलनी चाहिए इस समय, चुनाव का माहौल है।

...व्यवधान...

श्री महेंद्र गोयलः मैं कह रहा हूं कि बाकी की सारी चीजें एक तरफ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इसी पर चर्चा हो जाए, इलैक्ट्रोल बॉड के ऊपर किस-किस पार्टी को, किस-किस प्रकार से दिए गए, इसके ऊपर हम सदन के अंदर चर्चा चाहते हैं।

माननीया अध्यक्षः गोयल जी बैठिए मैं चीफ व्हिप के साथ चर्चा करके आपको संदेशा भिजवा देंगे कि किस दिन बुलाया जाएगा सदन इस संदर्भ में, बैठिए। अब श्री मदनलाल जी दिल्ली में असंवैधानिक रूप से राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे, मदनलाल जी।

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)

श्री मदनलालः धन्यवाद अध्यक्षा जी, आपने मुझे इस ज्वलंत विषय पर बोलने की अनुमति दी आपका धन्यवाद। अध्यक्षा जी जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लगातार लोगों के हितों के लिए काम करती आ रही है और बीजेपी की लाख कोशिशों के बाद भी ये सरकार तीन बार बन गई है, बीजेपी इससे बहुत परेशान है और लगातार कोशिश करती है कि किसी भी तरह दिल्ली की ये सरकार, या तो ना बने या अपदस्थ कर दी जाए। इसीलिए अब आजकल एक और नई चर्चा शुरू हो गई है कि जब से माननीय केजरीवाल जी 21 मार्च से ईडी ने गिरफ्तार किए हैं उसके बाद लगातार बीजेपी कोशिश करती रही है कि वो इस्तीफा दे दे जिससे सरकार का कामकाज ठप्प हो जाए। इस पार्टी के एमएलएज में अफरातफरी हो और बीजेपी का जो लगातार पर्यत्न रहा है कि किसी भी तरह साम, दाम, दंड, भेद से अपने संख्या बल को बढ़ाया जाए। इस संख्याबल को बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार कई तरह से पर्यत्न करती रही है। इस तरह राष्ट्रपति शासन की जो तैयारी चल रही है, उसकी वजह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरूपयोग होने लगा है और दिल्ली में अघोषित एमरजेंसी जैसा माहौल पैदा हो गया है। एलजी साहब सार्वजनिक मचों से कहते सुने जा रहे हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे। ये जहां एक और राष्ट्रपति के पद की गरिमा पर कुठाराघात है वहीं दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों का भी हनन करने की कोशिश है। अध्यक्षा जी अगर हम देखें तो पूरे देश में इस समय 28

राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें से 17 पर बीजेपी काबिज है। 2014 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद उनकी लगातार कोशिश रही कि उनका संख्या बल किसी भी हालत में कम ना हो। परन्तु उनके झूठे वायदे, लोगों की निराशा ने लोगों को उस पार्टी से मोह भंग कर दिया। जहां एक और उन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए के कहीं उनका संख्या बल कम ना हो जाए, लगातार कोशिश की और हमें अच्छी तरह याद है कि उनके एक स्वामी पर जो एमपी थे, रेप के चार्जिज लगे। हनीट्रैप के नाम पर उस वकील के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कराया गया जिससे उनका एक एमपी कम ना हो। हमारी पहलवान लड़कियाँ, जो देश की गौरव रहीं, जिन्होंने देश का मान-सम्मान बढ़ाया, जब उनके molestation की बात आई, लगातार वो दिल्ली में प्रदर्शन करती रहीं, उनके हक में लोग प्रदर्शन करते रहे, परन्तु अपने एमपी को बचाने के लिए उन्होंने कोई कार्रवाई ना होने दी। किसानों के पिछले आंदोलन में 4 किसानों की निर्मम हत्या उनके डिप्टी होम मिनिस्टर के बेटे ने कर दी, कोई एक्शन नहीं लिया। ये एक तरह का कर्त्तव्य था उनका, एक तरह का काम था कि संख्या बल बीजेपी का कम नहीं होना चाहिए और दूसरा उन्होंने काम क्या किया, कि हिन्दुस्तान में चुन-चुनकर ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं उन्हें लगे की ये बरगलाए जा सकते हैं, डराए जा सकते है, उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करना शुरू कर दिया और शामिल खुशी से नहीं किया, खुशी से कोई होता भी नहीं। उन्होंने उसके लिए अपने जो दो बड़े दफ्तर हैं, जो बड़े डिपार्टमेंट है, एक सीबीआई और एक ईडी, उनका सहारा लेना

शुरू कर दिया। 2018 में उन्होंने इलैक्ट्रोरल बाँड नाम से एक स्कीम चालू की। इलैक्ट्रोल बाँड की पहली शर्त रखी गई की ये गुप्त होगा, ये गुप्तदान होगा, आरटीआई के दायरे में भी नहीं आएगा और एसबीआई के थ्रू, जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके थ्रू उन्होंने इलैक्ट्रोल बाँड बेचने शुरू करा दिये। पहली शर्त थी गुप्त रहेगा, किसी को कानोंकान खबर नहीं होगी, कौन सी कम्पनी ने दिया, किसको दिया, कोई उसके बारे में चर्चा नहीं होगी और कोई उसके बारे में जांच-पड़ताल भी नहीं होगी। मैं धन्यवाद करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायधीशों का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में पांच जजों की बैंच ने 15 फरवरी, 2023 को उस काले कानून को, उस काले इलैक्ट्रोल बाँड की स्कीम को खत्म कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया और साथ ही साथ आदेश दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बताए कि वो कौन सी कम्पनियाँ हैं, कौन से लोग है जिन्होंने पोलिटिकल पार्टीज को चंदे के रूप में चंदा दिया है। अध्यक्षा जी, हमारे देश में काफी पोलिटिकल पार्टियाँ हैं, इनमें से 6 नैशनल पार्टी हैं और 57 स्टेट पार्टीज हैं, कुल मिलाकर 63 पार्टी हैं। अगर हम देखें तो चंदे का जो सबसे बड़ा पोर्शन वो अकेली बीजेपी पार्टीको 57 परसैंट इलैक्ट्रोल बाँड के रूप में फंड मिला। 12000 करोड़ रुपया के इलैक्ट्रोल बाँडस इन कम्पनियों ने, ओर्गेनाइजेसंस ने और व्यक्ति विशेषों ने खरीदे। उसका 57 परसैंट 6986.5 करोड़ रुपया अकेली बीजेपी को मिला। ये 12000 करोड़ में से था जो 57 परसैंट बैठता है। हिन्दुस्तान की दुसरी सबसे बड़ी पार्टी काँग्रेस को महज 10 परसैंट मिला।

17 राज्य बीजेपी के कब्जे में, 7 राज्य जिनमें तीन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में काँग्रेस की सरकार है और दो में वो तमिलनाडू और झारखंड के साथ, सरकार साझा करते हैं, उनको मात्र 10 परसैंट। पर ये क्या कारण था कि 57 परसैंट इलैक्ट्रोल बाँड का पैसा, जो लगभग 7 हजार करोड़ रुपए के करीब बैठता है वो बीजेपी को मिला। इस देश में 5 बड़ी कम्पनियाँ हैं, 4 बड़ी कम्पनियाँ, सिपला-रेमेंडेसिविर बनाती थी और दवाईयाँ भी हैं बहुत। अगर हमें याद हो तो कोरोना में सबसे ज्यादा डिमांड रेमेंडेसीविर की हुई। अध्यक्षा जी उस कम्पनी का रेमैंडेसीविर का सैंपल फेल हुआ और बड़ी सरकार ने उसकी बाँह मरोड़ते हुए 37 करोड़ रुपए का चंदा लिया। क्या ये चंदा था? हम कई बार इलैक्शन में अपने कई साथियों को देखते हैं कि हम आपकी तन-मन-धन से मदद करेंगे। तन-मन-धन में वो कहते हैं कोई जरूरत हो तो हमें बता देना धन की भी, जो हमारे हितैषी होते हैं। पर ऐसे लोग जो हमारे हितैषी नहीं है, जो किसी कारणवश, डर के, भय के कारण अगर किसी पार्टी को देते हैं, जो यहां साफ नजर आ रहा हैकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास ईडी और सीबीआई जैसे अधिकार हो, उसको अगर 57 परसैंट का दान कोई कम्पनियाँ दे रही हैं तो शक के दायरे में आती हैं। अध्यक्षा जी, सिपला ने 37 करोड़ रुपया, सनफार्मा ने साढ़े 31 करोड़ रुपया, डिवीस लैब्रोटरीज ने 30 करोड़ रुपया और डॉ. रेडी ने 25 करोड़ रुपया बीजेपी को इलैक्ट्रोल बाँड के रूप में दिया। ये क्या कारण था कि ये कम्पनियाँ इतनी ज्यादा दयालु हो गईं कि केवल बीजेपी को दे रही थी या इसके पीछे उन

कम्पनियों का डर था, जो ईडी के माध्यम से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, ये जांच का विषय है। देश की 15 कम्पनियों में जो सबसे बड़ी हैं, 15 कम्पनी इस लिस्ट में, 13 कम्पनियों ने बीजेपी को चंदा दिया, आप सोचें 15 कम्पनी, 13 ने बीजेपी को चंदा दिया केवल। अध्यक्षा जी, निफ्टी और सैंसेक्स कम्पनीज ने अपना 81 परसैंट का इलैक्ट्रोल बाँड आप समझो 19 परसैंट दूसरे लोगों को और अकेली बीजेपी को अपना पूरा इलैक्ट्रोल बाँड का 81 परसैंट हिस्सा केवल बीजेपी को दिया। अध्यक्षा जी अपने लोगों की गिनती बढ़ाने को जब कोई नहीं मानता था, प्यार से बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा था तो इन्होंने ईडी का सहारा लिया और ईडी का सहारा लेकर 2014 से 2024 तक 25 prominent दूसरी पार्टियों के लीडर्स जिनमें से 10 काँग्रेस के, 4 एनसीपी के, 4 शिव सेना के, 3 टीएमसी के, 2 टीडीपी के, 1 समाजवादी पार्टी और एक टीवाईएसआरएससीपी इन लोगों को अपने यहां जगह दी।

माननीया अध्यक्षः मदन लाल जी आपका फ्लो बहुत अच्छा है, भूमिका बहुत लम्बी बन गई है, मुझे लग रहा है विषय से थोड़ा सा भटक रहे हैं आप।

श्री मदन लालः सिर्फ दो मिनट।

माननीया अध्यक्षः नहीं आप बोलिये लेकिन विषय पर आ जाइये।

श्री मदन लालः मैं विषय पर ही आ रहा हूं।

माननीया अध्यक्षः जी।

श्री मदन लाल: यही विषय है।

माननीया अध्यक्ष: भूमिका बहुत लम्बी हो गई है।

श्री मदन लाल: आफटरआल राष्ट्रपति शासन की जो अभी हमने, जो डर पैदा किया जा रहा है दिल्ली मे, मैडम वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल इसीलिए भेजा है कि ये पार्टी टूटे। राष्ट्रपति शासन क्यों होगा कि इसकी जो दिल्ली सरकार अभी अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी ना चलाकर एलजी महोदय चलाएं और एलजी महोदय किसके behalf पे एक्ट कर रहे हैं, बीजेपी के और बीजेपी ये क्यों कर रही है, क्योंकि उन्होंने कलांतर में जो-जो लोग अपने यहां डरा-डरा के शामिल किए हैं, अरविंद केजरीवाल जी अगर शामिल हो जाते, अगर मनीष सिसोदिया जी शामिल हो जाते, अगर जैन साहब शामिल हो जाते तो ये नौबत थोड़े ही आती। संजय सिंह जी अगर बीजेपी में शामिल हो जाते, तो गिरफतार ही ना होते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, ईडी ने साफ कहा है कि हमारे पास इनके लिए, इस समय कोई और साक्ष्य जो डायरेक्टली लिंक करता हो मनी ट्रेल का वो नहीं है। अध्यक्षा जी यही कारण था कि लगातार उनकी जब स्कीम फेल हो जाती थी, 95 परसैंट लोग केवल और केवल विपक्ष के हैं जिनपर ये मुकद्दमें हैं। उनमें से जो 25 आए, 20 के खिलाफ मुकद्दमें उन्होंने कोल्डस्टोरेज में डाल दिए हैं, उनपर इनवैस्टीगेसन बंद हो गई है, शांत हो गई है, जब जरूरत होगी तब करेंगे। तीन के मुकद्दमें उन्होंने खत्म कर दिये हैं, केवल दो के मुकद्दमें चल रहे हैं। अध्यक्षा जी, सुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, अर्चना

पाटिल, अशोक चव्हान, हेमंत विस्वा शर्मा, भावना गामिक, अजीत पवार, फ्रुल्ल पटेल ये ऐसे-ऐसे नाम है जो करप्शन में घिरे हुए थे, पर चूंकि बीजेपी में शामिल हो गए, सबके गुनाह माफ कर दिये गए। सिर्फ इसी इलैक्शन से पहले 6 prominent leaders ने बीजेपी का हाथ थामा है। अगर यहां हमारी पार्टी के लोग भी आपने पीछे का एपीसोड देखा होगा। हममें से कुछ लोगों ने कहा कि हमें 25-25 करोड़ की ऑफर दी गई है। ये केवल और केवल इस सरकार को derail करने की कोशिश थी, इस सरकार को कैसे खत्म किया जाए, इस सरकार को कैसे काम करने से रोका जाए उसके लिए शाम-दाम-दंड-भेद, अगर प्यार से नहीं मानते तो पैसे से मानेंगे, पैसे से नहीं मानेंगे डर से मानेंगे और डर से भी नहीं मानें तो राष्ट्रपति शासन से तो मानेंगे। आप इस चुनी हुई सरकार को बर्खाश्त कर दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो और लोगों को बता दो कि ये सरकार चलाने लायक नहीं है। ये सरकार घपलेबाज है। जबकि चंदे का 57 परसैंट, ये चंदा नहीं था। अगर चंदा होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट 15 फरवरी को इसे struck down नहीं करते। उन्होंने इस कानून को रद्द कर दिया और ये कहते कर दिया कि ये बेईमानी वाला कानून है, ये unconstitutional है। हमने रोज टेलीविजन में देखा है कि किस तरह एसबीआई के वकील ये कहते रहे कि इसमें तीन महीने लगेगें इस लिस्ट को आउट करने में, ये बताने में कि किस-किस कम्पनी ने किस-किस को कितना पैसा दिया है। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथी जजीज का धन्यवाद कि उन्होंने कहा कि दो दिन के भीतर लिस्ट आउट करके बताओ जो आज हम

यहां डिस्कस कर पा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने 5700 करोड़ रुपया, 57 अरब रुपया जिन कम्पनियों की बांह मरोड़-मरोड़ के और अगर देखें तो बहुत-बहुत लोग हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी के केस में जो सबसे बड़ा गवाह रेड्डी, 5 करोड़ रुपए उन्होंने दिए अपनी बेल कराने के, 55 करोड़ दिये अपने आपको मुकद्दमें से बरी कराने को। यहां केवल और केवल एक खतरा है कि क्या ये सरकार चलती रहेगी और अगर सरकार चलती रहेगी जैसा कि माननीय केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम जेल से भी चलाएंगे क्योंकि constitution में कोई प्रोविजन नहीं है कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकते। वो चिट्ठी लिखकर आदेश दे सकते हैं और आज के दिन तो आचार संहिता लगी हुई है। कोसिंल ऑफ मिनिस्टिर्स की तो मीटिंगस ही नहीं हो सकती। तब अब आज काहे के लिए ऐसी चर्चाएं हो रही है, आज क्यों कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन की ओर अग्रसर है? ये केवल डराने-धमकाने के लिए हो रहा है, क्योंकि ये पार्टी साम-दाम और भेद से नहीं मान रही है इसलिए दंड़ात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है। हम इसकी भर्तस्ना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बड़ी सरकार को समझ आयेगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद लोगों का समूह और सारे के सारे लोग आज के दिन आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो गये हैं। हमें लगता है अगर बीजेपी ने ऐसा कोई कदम उठाया तो ये उनके लिये बहुत ज्यादा और ज्यादा घातक साबित होगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः अखिलेश पति त्रिपाठी जी।

श्री राजेश गुप्ताः माननीया अध्यक्षा जी मैं बीच में एक बात रखना चाहता हूं माननीय मैम्बर संजीव जी ने एक बात रखी कि किस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष, दिल्ली के अध्यक्ष आये हुये हैं और गांधी जी की मूर्ति के बाहर एक ड्रामा कर रहे हैं। इस विधानसभा की sanctity को खराब करने का जो ये तरीका है ये बहुत ही गलत है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके ऊपर आप संज्ञान लें, इसे किसी कमेटी में भेजें क्योंकि ये दोबारा नहीं होना चाहिये।

माननीया अध्यक्षः बैठिये।

श्री राजेश गुप्ताः इस बात के लिये मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं, धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः बैठिये, हालांकि ये बहुत गंभीर विषय है और ये प्रस्ताव जो संजीव झा जी ने रखा ये सदन के समक्ष है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

यह प्रस्ताव पास हुआ।

तो ये मामला मैं प्रिविलेज कमेटी को रेफर करती हूं और प्रिविलेज कमेटी इसका संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी इस पर कार्यवाही शुरू करे। अखिलेश पति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: धन्यवाद सभापति महोदया, आपने दिल्ली के विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिये हिस्सेदार बनाया। मैं अपनी बात दो लाइनों से शुरू करूंगा:

"धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है
ये धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है
ना पूरे शहर पर छाये तो कहना
ना पूरे शहर पर छाये तो कहना,
देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जायेंगी लाशें
देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जायेंगी लाशें,
ढूंढोगे तो इस शहर के कातिल ना मिलेंगे
ढूंढोगे तो इस शहर के कातिल ना मिलेंगे।"

इस शहर के कातिल कौन हैं? पूरे दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने एक सरकार चुना will of power represent करने के लिये और उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में शासन करने लायक नहीं समझते इसलिये हम अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताते हैं। उन्होंने शानदार मोहल्ला क्लीनिक का मॉडल दिया है, हम तिबारा भी मौका देंगे। दिल्ली के लोगों ने फिर 2020 में मौका दे दिया। अरविंद केजरीवाल ने नायाब सरकारी शिक्षा का मॉडल दिया, हम अरविंद केजरीवाल में भरोसा जताते हैं। दिल्ली के लोगों ने कहा कि

हम दिल्ली सरकार के केजरीवाल मॉडल के, बिजली के मॉडल से जो सबको निःशुल्क बिजली मिल रही है उससे सहमत हैं, हम इस सरकार में विश्वास जताते हैं। हम उस दिल्ली में विश्वास जताते हैं जो निःशुल्क पानी 20 हज़ार लीटर घर-घर तक पहुंचाने का संकल्प दोहराता है। हम उन महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराने वाली सरकार के संकल्प के साथ हैं, दिल्ली के लोगों ने साथ दिया। बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने के मजबूत इरादे अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने साथ दिया। उन्होंने door step delivery of services घर-घर सरकार की सेवायें देने वाली सरकार का साथ दिया। जब ये मॉडल बन गया और धीरे-धीरे ये मॉडल दिल्ली से बाहर जाकर के पंजाब तक पहुंचा, इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया सभापति महोदया और ये मॉडल की खुशबू जब पंजाब में पहुंची तो सरकार बन गई, 117 में से 93 सीटों के साथ सरकार बनी और वहां 92वे, मदन लाल जी कह रहे हैं 92वे सीटों के साथ सरकार बन गई। इनकी ज़ीरो सीटें हो गईं, पेट में दर्द होना शुरू हो गया। यहां पर जो Door Step Delivery of Ration का स्कीम मुख्यमंत्री जी ने चलाया था उसको यहां पर भारतीय जनता पार्टी के एल.जी. के माध्यम से, केन्द्र की सरकार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने रोका, उसको पंजाब में हमने लागू करके दिखाया कि अगर इच्छा शक्ति हो, ईमानदार नेतृत्व हो तो उसको लागू किया जा सकता है, वहां पर भगवंत मान की सरकार ने लागू किया। अब वो मॉडल, केजरीवाल मॉडल इनको चुनौती बन गई है। अब इन्होंने कहा कि क्या करें कि अरविंद केजरीवाल को हटायें। ये मॉडल गुजरात तक

पहुंच गया, वहां भी 17 परसेंट वोट मिल गया, 5 विधायक आ गये, ये मॉडल गोआ तक पहुंच गया, ये केजरीवाल को रोकें कैसे, वहां पर भी विधायक आ गये। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ये बताओ केजरीवाल को कैसे रोकें, कुछ सूरत इनको भारतीय जनता पार्टी को नज़र नहीं आ रही थी और यहीं तक रथ नहीं रूका, केजरीवाल मॉडल ऑफ गर्वनेंस ने ये बता दिया कि सब कुछ निःशुल्क देकर के भी मुनाफे में कैसे सरकार चलाई जा सकती है, ईमानदार सरकार कैसे चलाई जा सकती है। जब ये चुनौती बनी और वो चुनौती इनके 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन को एमसीडी में खत्म कर दिया, तब इनको सहा नहीं गया, तब नहीं रहा गया। अध्यक्षा महोदया, इन्होंने झूठा केस बनाया, बोला शराब घोटाला हो गया, दिल्ली में शराब घोटाला हो गया। खुद दिल्ली में दिल्ली के बाहर से बार्डर से इल्लीगल शराब लाकर के भारतीय जनता पार्टी गुजरात का मॉडल जो गुजरात में एक रूपये का दारू नहीं बिकता, सरकार की तरफ से जहां बैठिये वहां पर पांच मिनट के अंदर मिल जाता है, तो हमने बोला कि ये कौन सा दारू बिकने का मॉडल है। वैसे सरकार तो बेचती नहीं, मना है पूरे राज्य में लीकर बेचना, ये दारू कैसे मिलता है गुजरात में, बोले वो तो सरकार की तरफ से बंद है क्योंकि उसको सरकारी जब लीकर बिकता है उसके लाइसेंस की पॉलिसी बनती, तो उसका पैसा सरकार के खजाने में आता और वो पैसा जनता की भलाई में लगता लेकिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का एक नायाब तस्करी का मॉडल है।

माननीया अध्यक्षः त्रिपाठी जी विषय पर रहें, विषय पर रहें।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः नया दलाली का मॉडल है। स्पीकर महोदया, जरा सुनियेगा, इन्होंने कुछ अपने चंद दलाल छोड़ रखे हैं, तस्कर छोड़ रखे हैं गुजरात में तस्करी कराकर दारू बिकवाते हैं, 25 हज़ार करोड़ से ज्यादा का पैसा इनके दलालों के खातों में जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में इलैक्शन, इलैक्ट्रोल बांड के रूप में आता है, अध्यक्षा महोदया ये भी खुलासा होने वाला है, ये भी खुलासा होने वाला है। वही मॉडल दिल्ली में लागू करना चाहते हैं। आज भी, हर गली-मोहल्ले में जाईये कहीं छोटी जगह पर इनकी पुलिस के माध्यम से खुलेआम छोटे-छोटे जगहों पर दारू बिकवाने का काम होता है और आरोप आप अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पर लगाते हो। अरे money trail की बात करते थे, दारू का घोटाला हो गया है, दो साल ई.डी. लगी रही आपको कुछ नहीं मिला। वो money trail कहां मिला, भारतीय जनता पार्टी के Electoral Bond के खाते में मिला। पेट में दर्द था, एक ईमानदार आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो क्योंकि ये ब्रांड अरविंद केजरीवाल ईमानदार ब्रांड बनकर निकले हैं, उसके ब्रांड को कुछ धब्बा लगाओ। भारतीय जनता पार्टी वालो सुन लो, हम लोग नेक इरादे वाले लोग हैं, ईमानदार नियत वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार दिल्ली में चलाई है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में एक नायाब मॉडल दिया है और आपकी तानाशाही के खिलाफ झुकेंगे नहीं, जेल से भी सरकार चलाकर एक नायाब मॉडल देश को देंगे कि देश में तानाशाही जब भी हावी होगी, ईमानदार सरकार को झुकाने की कोशिश की जायेगी, हम झुकेंगे

नहीं, सरकार जेल से भी चलाकर दिखायेंगे और उसका जीता-जागता नमूना देखिये, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो आदेश जारी कर दिये हैं, एक हमारी जल मंत्री आतिशी जी को जारी किया रविवार को और एक बुधवार को हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जारी किया कि दिल्ली के लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिये, आप जाकर के जल के मामले में जो भी है उसमें कमी ना हो, सारी चीज़ें ठीक रहें और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को कहा कि जाकर दवाईयों की उपलब्धता जो कम है, जहां कमी हो रही है, उसको देखें। तो सरकार चलायेंगे और साथ-साथ में दो चीज़ें और रह गई हैं छोटी-छोटी, छोटी-छोटी दो चीजें रह गई हैं।

माननीया अध्यक्षः कम्प्लीट करिये।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं कि आपने xxxx[2] छोड़ रखा है, ये xxxx[2] को छोड़ रखा है। 27 तारीख को एल.जी. साहब एक चैनल पर जाते हैं। अब भई भारतीय जनता पार्टी का एल.जी. है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के गर्वनर कभी न्यूज़ चैनल पर जाते होंगे। आपने सुना होगा कभी गुजरात के गर्वनर कभी न्यूज़ चैनल पर जाते हों, आसाम के गर्वनर तो जाते होंगे, नहीं जाते, कमाल है। ऐसा xxxx[2] छोड़ रखा है कि न्यूज़ चैनल पर जाकर और बोलते क्या हैं कि मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करता हूं, दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, xxxxxx[2], तुमने चुना था सरकार? दिल्ली के लोगों ने चुना था। होश में रहो। दिल्ली के लोगों ने तुमको एमसीडी में हराकर

[2] चिन्हित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाए गए।

भेजा, तीन बार से तुमको हरा रहे हैं दिल्ली में। लोकसभा में हराकर कन्क्लूड कर देंगे तुमको। तुम्हारी हिम्मत है तो राष्ट्रपति शासन लगाकर दिखाओ। तुम्हारी हिम्मत है? दिल्ली के लोगों को कुचलने की कोशिश कर रहे हो, दिल्ली के लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हो xxxxxxxx[2] वो चुने हुये सरकार को, दिल्ली के लोगों को, जनता को उनको हड़काने का कोशिश कर रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूं जेल में जब से मुख्यमंत्री जी गये हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के जैसे बांछें खुल गई हैं, कब दोगे इस्तीफा, कब दोगे इस्तीफा, कब दोगे इस्तीफा, कब दोगे इस्तीफा। अरे, इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलायेंगे। हिम्मत हो तो कोई मॉडल बनाकर दिखाओ जो मोहल्ला क्लीनिक से बढ़िया हो जाये, हिम्मत है तो दिखाओ कि बिजली फ्री करके दिखाओ फिर भी मुनाफे में सरकार चलाकर दिखाओ। एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, 16 जगह सरकारें हैं, जहां पर मुनाफे की सरकार चल रही है, सब जगह घाटे में है। यहां पर ईमानदार सरकार है इसलिये मुनाफे में चल रहे हैं और सब कुछ फ्री दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को, वहां पर तुम लोग कुछ नहीं दे पा रहे हो क्योंकि वहां पर बेईमान सरकार है, एक मिनट और लगेगा। ये लोग कहते हैं राजनितिक, ये राजनीतिक टिप्पणी से राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है दिल्ली में, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने हैं कि अब्दुला की शादी में बैगाना दिवाना, ये हालत है। सरकार हम चला रहे हैं, सरकार का मामला हमारा है, पहले कूद रहे हैं नहीं जी, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, हम

---

[2] चिन्हित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाए गए।

नहीं चलने देंगे। तुम कौन हो भई, तुम कौन हो? कोट सिलवा रहे हैं, मदन लाल जी कह रहे हैं कोट सिलवा रहे हैं अभी से राष्ट्रपति शासन लगाने के लिये। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछता हूं कि कोर्ट गये थे लोग, कोर्ट ने कहा कि सरकार को जेल से चलने के लिये कोई भी संवैधानिक, कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, कहीं कानून में नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है, इसलिये हम जो ये पीआईएल आया है इसको रिजेक्ट करते हैं। और संवैधानिक विशेषज्ञ भी हैं, इसी सदन के सचिव भी रहे हैं और लोकसभा के भी वहां सचिव रहे हैं एस.के. शर्मा जी उन्होंने कहा कि कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है जो कहता है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जेल से भी सरकार चला सकते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कुचक्र रच रही है। पद पर बने रहने को लेकर के कोर्ट ने पूछा।

माननीया अध्यक्षः चलिये बहुत-बहुत धन्यवाद और भी वक्ता हैं।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः क्या मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिये कोई कानूनी बाध्यता है?

माननीया अध्यक्षः त्रिपाठी जी बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः भारतीय जनता पार्टी बता नहीं पाई। आज मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी जिस दिन हेमंत विश्वा शर्मा जी का इस्तीफा ले लेगी, जिस दिन, जिस दिन अजय टैनी का

जो इनके किसानों के हत्यारा, हत्यारे परिवार से हैं, जिनके बेटे ने हत्या किया।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद, बस-बस।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः उनका इस्तीफा ले लेंगे, जिस दिन आदर्श घोटाला वालों का इस्तीफा ले लेंगे, जिस दिन मुकुल राय जी का, शुभेंदु अधिकारी जी का इस्तीफा ले लेंगे, जिस दिन अजीत पवार जी का इस्तीफा ले लेंगे, जिस दिन ये, जिस दिन ये, जिस दिन ये अपने जितने भ्रष्टाचारी हैं अपनी पार्टी में लिये हैं उनका इस्तीफा ले लेंगे, उसके बाद बात करना। ये लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि हम करें, बीजेपी करे तो xxxxxxxx[2] और कोई करे तो xxxxxxxx[2]। हम खेलें तो गिल्ली-डंडा और तुम खेलो तो क्रिकेट, ये नहीं चलेगा देश में।

माननीया अध्यक्षः चलिये बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः देश के लोग देख रहे हैं की आप लोग ताबूत में घोटाला करने वाले लोग हो, आप लोग पीएम केयर में घोटाला करने वाले लोग हो। आप लोगों के पीएम केयर के भी घोटाले का भी खुलासा होगा और देश..

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद, अखिलेश पति त्रिपाठी जी द्वारा जो आपत्तिजनक शब्द बोले गये हैं, उसको कार्यवाही से निकाल दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बंद कर दीजिये, बैठिये, बी.एस. जून साहब। अपना वक्तव्य रखते वक्त, अपना वक्तव्य रखते वक्त शब्दों की मर्यादा

[2] चिन्हित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाए गए।

का ध्यान रखें, मर्यादित आचरण रखें, जो शब्द आपत्तिजनक हैं उसे कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री बी.एस. जून: धन्यवाद मैडम, जो मुझे बोलने का अवसर दिया। ये बात ठीक है कि आज एक डर का माहौल बनाया जा रहा है कि दिल्ली की एसेम्बली को या तो भंग कर दिया जायेगा या उसको suspended animation में डाल दिया जायेगा। अभी-अभी न्यूज़ आई कि डराने के लिये, धमकाने के लिये एक और विधायक को आज 2.00 बजे ई.डी. ने समन कर लिया दिया दुर्गेश पाठक जी को और वैभव कुमार जी को उनको आज बुलाया है उनकी interrogation चल रही है। मैडम क्या ऐसी सिचुएशन दिल्ली में है कि इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाये, ऐसी सिचुएशन आज है कहीं, कोई पोलिटिकल क्राइसिस है दिल्ली में? नहीं है। पब्लिक ने जबरदस्त मैन्डेट दिया, आज भी 62 विधायक अरविंद केजरीवाल जी के पीछे सॉलिड रॉक की तरह खड़े हुये हैं। क्या दिल्ली में कोई constitutional crisis है जिससे राष्ट्रपति शासन लगाया जाये? बिल्कुल नहीं है अब राष्ट्रपति शासन लगाने की कंडीशन क्या है मैं सिर्फ दो लाइन पढ़ूंगा आर्टिकल-356 की 'if Governor is satisfied that a situation has arisen in which the Government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution.' सरकार Constitution के प्रावधानों के तहत काम नहीं कर रही है। अब उसके मैं तीन उदाहरण देता हूं मैडम, आज ही दिल्ली हाई कोर्ट ने और उससे पहले दो बार दिल्ली हाई कोर्ट तीन पेटिशन डिस्मिस कर चुकी है जिसमें ये कहा गया था

कि मुख्यमंत्री को हटाया जाये और हाई कोर्ट ने कहा कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसमें मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकते। इसका मतलब Constitution की कोई वॉयलेशन नहीं हो रही है और अगर Constitution की वॉयलेशन नहीं हो रही है तो फिर Constitutional crisis इस दिल्ली में नहीं है और अगर वो नहीं है तो किसी भी कॉस्ट पर वो नहीं लगाया जा सकता राष्ट्रपति शासन या suspended animation की बात नहीं की जा सकती। अब मैडम Constitutional crisis कैसे होगा? नम्बर-(1) कि सरकार माइनॉरिटी में है, बिल्कुल नहीं है, 62 विधायक हैं। नम्बर-(2) State में Law & Order की सिचुएशन बहुत बुरी है। उस पर हम डिस्मिस हो ही नहीं सकते, Law & Order हमारे पास नहीं है। उस पर तो सैन्ट्रल गर्वमेंट डिस्मिस होनी चाहिये, सैन्ट्रल गर्वमेंट डिस्मिस होनी चाहिये ना कि दिल्ली सरकार। नम्बर-(3) क्या गर्वमेंट ने कोई, दिल्ली गर्वमेंट ने ऐसा कोई कानून पास किया है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाये गये कानून के विपरीत हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। चौथी बात, क्या दिल्ली सरकार ने सैन्ट्रल गर्वमेंट का कोई lawful order मानने से इन्कार कर दिया, वो भी नहीं है। क्या दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई काम किया कि भई Apex Court, सुप्रीम कोर्ट को हम चैलेंज कर रहे हैं या इण्डिया की sovereignty को हम चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर राष्ट्रपति शासन लगाने का उनका ग्राउंड क्या है?

...व्यवधान...

श्री बी.एस. जून: राष्ट्रपति शासन किन स्टेट्स में लगना चाहिये था? राष्ट्रपति शासन लगना चाहिये था मणिपुर में जहां एक कारगिल के हीरो की वाइफ को निर्वस्त्र करके और पूरे शहर में घुमाया गया। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिये था महाराष्ट्र में जहां एक इलीगल सरकार चल रही है स्पीकर की मदद से, स्पीकर ने उन विधायकों को expel नहीं किया जो disqualification में आते थे, उनको बचा लिया गया और आज वो इलीगल सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। मैडम दूसरी बात है क्या किसी frivolous ground पर आप सरकार को डिस्मिस कर सकते हैं, President's Rule लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बार-बार सूप्रीम कोर्ट ने कहा, 1980 में आर्टिकल-356 में जबरदस्त अमेंडमेंट हुआ कि कोई भी सरकार ऐसे डिस्मिस नहीं हो सकती। फिर भी अगर ये अपनी मनमानी करते हैं, सरकार को डिस्मिस करने की कोशिश करते हैं President's Rule लाते हैं तो ये एक मतलब इन्हीं के ऊपर वो बात आयेगी और मुझे लगता है अगली बार इनका एक भी एमएलए नहीं आयेगा बीजेपी से, ऐसी सिचुएशन आ जायेगी। दूसरी बात मैडम, ये कहते हैं एक ग्राउंड हो सकता है कि सीएम कस्टडी में चले गये। तीन बार हाई कोर्ट ने कहा कि सीएम जेल से काम कर सकते हैं, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। तो Constitution में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। त्रिपाठी जी ने कहा सीएम के वहां से जेल से message आ रहे हैं, इन्फोर्मेशन आ रही है डायरेक्शन्स आ रही है और मंत्री स्मूद्ली काम कर रहे हैं, कोई काम रूका हुआ नहीं है। मदन लाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि Model Code of Conduct है तो 4 जून तक

कोई policy decision नहीं हो सकता, उसमें कोई कैबिनेट मीटिंग की जरूरत नहीं है। तीसरी बात मैडम, अब आते हैं कि सीएम जेल में कैसे काम करेंगे? सहारा ग्रुप के सुब्रतो राय को बदरपुर रोड़ पर एक प्राइवेट बिल्डिंग को दिल्ली सरकार ने जेल नोटिफाई किया और जेल नोटिफाई करने के बाद उनका पूरा स्टाफ वहां बैठा, जेल वाले उनको वहां सुबह ले जाते थे शाम को लेकर आते थे और उन्होंने अपना ऑफिस रन किया वो हमारे केस में भी हो सकता है। हमारे सीएम को भी एक अलग जगह पर जेल नोटिफाई कर दें और वहां से सीएम ऑफिस चलेगा कैबिनेट मीटिंग होंगी, फाइलें निकलेंगी। सैकेंड केस यूनिटैक बिल्डिर्स का है उनके लिये तिहाड़ जेल में ही सैपरेट जेल नोटिफाई की गई और उन्होंने बैठकर वहां काम किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा डिसिजन नहीं है, कोई भी ऐसा स्टैप नहीं है जिन से दिल्ली में President's Rule लगाने की या suspended animation में जाने की नौबत आये। तो ये एक डराने की बात है। इलैक्शन में जीत नहीं सकते, कि डराओ-धमकाओ, पार्टी को तोड़ो, गर्वमेंट को तोड़ो। ये इतने सख्त 62 एमएलएज़ आज भी बिल्कुल एक चट्टान की तरह खड़े हुये हैं अरविंद केजरीवाल जी के पीछे और किसी का कोई ऐसा डर नहीं है। तो उनके पास ये सिर्फ डराने की बात है, मैं नहीं समझता वो इतना extreme step लेंगे क्योंकि नुकसान उन्हीं को होगा, हमें तो डबल फायदा होगा। 2.00 बज गये हैं, सवा दो बज गये है मैं बोल और भी सकता था लेकिन आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक्यू वेरी मच।

माननीया अध्यक्षः चलिये जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करूं, स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुये मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, सभी मंत्रीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष, रामवीर सिंह बिधुड़ी तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूं। इसके अलावा सत्र के संचालन में सहयोग देने के लिये विधानसभा सचिवालय तथा दिल्ली सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों और सुरक्षा एजेंसियों तथा मिडिया का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वे राष्ट्र गान के लिये खड़े हो जायें।

राष्ट्र गान

माननीया अध्यक्षः अब सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित की गई।)

...समाप्त....

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।